● वर्ष-3
● अंक-157
रायपुर, शुक्रवार
09 फरवरी 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल..

यूपीए ने 10 साल में इकोनॉमी को नॉन-परफॉर्मिंग बनाया: सरकार

मोदी सरकार के श्वेत पत्र पर लोकसभा में चर्चा आज

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया. सरकार ने अपने श्वेत पत्र में 2014 से पहले और 2014 से बाद के भारत की इसकी अर्थव्यवस्था के फर्क को विस्तार से बताया है. मोदी सरकार ने अपने श्वेत पत्र में कहा कि यूपीए ने 10 साल में इकोनॉमी को नॉन-परफॉर्मिंग बना दिया है. श्वेत पत्र पर लोकसभा में शुक्रवार को चर्चा होगी. जबकि संसद के उच्च सदन राज्यसभा में श्वेत पत्र पर शनिवार को चर्चा होनी है.

श्वेत पत्र के जरिए, मोदी सरकार ने बताया कि साल 2024 से पहले देश के सामने कैसी आर्थिक और राजकोषीय चुनौतियां थीं. 2014 के बाद मोदी सरकार ने कैसे इन चुनौतियां का सामना किया और इसपर विजय हासिल की. सरकार ने अपने श्वेत पत्र को तीन भागों में बांटा है और ये रिपोर्ट 69 पेज की है. इसमें कांग्रेस के नेतृत्व में 2004 से 2014 की सरकार को यूपीए सरकार और 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए हमारी सरकार शब्द का इस्तेमाल किया है. श्वेत पत्र में कहा गया है कि यूपीए सरकार ने देश की आर्थिक नींव कमजोर की. यूपीए काल में भारतीय रुपये में भारी गिरावट हुई. 2014 से पहले देश में बैंकिंग सेक्टर संकट में था. विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी थी. तत्कालीन सरकार ने भारी कर्ज लिया था. यूपीए सरकार ने रेवेन्यू का गलत इस्तेमाल किया.

यूपीए सरकार में रक्षा क्षेत्र हुआ कमजोर

सरकार के श्वेत पत्र में कहा, यूपीए सरकार में रक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार और घोटालों के कारण निर्णय लेना रुक गया. इससे रक्षा तैयारियों से समझौता हो गया. सरकार ने आर्टिलरी और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, फाइटर जेट, सबमरीन, नाइट फाइटिंग गियर्स और कई इक्यूपमेंट के अपग्रेडेशन में देरी की.

कोल स्कैम का भी जिक्र

श्वेत पत्र में सरकार ने कोल स्कैम का भी जिक्र किया. सरकार ने कहा, 2014 में कोयला घोटाले ने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था. 2014 से पहले, कोयला ब्लॉकों का अलॉटमेंट पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमाने आधार पर किया गया था. कोयला क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता से बाहर रखा गया था. इस क्षेत्र में निवेश और दक्षता का अभाव था. इन कार्रवाइयों की जांच एजेंसियों द्वारा जांच की गई. 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से आवंटित 204 कोयला खदानों/ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया. श्वेत पत्र में सरकार ने कहा, यूपीए सरकार के शासन का दशक नीतिगत दुस्साहस और सार्वजनिक संसाधनों (कोयला और दूरसंचार स्पेक्ट्रम) की गैर-पारदर्शी नीलामी, पूर्वव्यापी कराधान, अस्थिर मांग प्रोत्साहन और गैर-लक्षित सब्सिडी और लापरवाही जैसे घोटालों से चिह्नित था. 122 दूरसंचार लाइसेंसों से जुड़ा 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से सरकारी खजाने से 1.76 लाख करोड़ रुपये की कटौती की गई थी. इन घोटालों ने बढ़ते राजनीतिक अनिश्चितता के माहौल का संकेत दिया और एक निवेश को लेकर भारत की छवि पर खराब असर डाला.

मोदी सरकार के श्वेत पत्र की खास बातें– सरकार ने श्वेत पत्र में कहा, 2014 में जब एनडीए सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब देश की अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में ही नहीं थी, बल्कि संकटग्रस्त थी. हमने एक दशक के लिए कुप्रबंधित अर्थव्यवस्था को ठीक करने और इसके मूल ढांचों को मजबूत स्थिति में बहाल करने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना किया. सरकार ने कहा कि 2014 में भारत दुनिया के 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था. अब हम शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं. भारत की अर्थव्यवस्था हर साल ग्लोबल इकोनॉमी में तीसरा सर्वाधिक योगदान देती है. सरकार ने कहा कि 2014 से पहले और इसके कुछ बाद के कुछ समय में दुनिया का भारत की आर्थिक क्षमता और गतिशीलता से भरोसा उठ गया था. अब हमारी आर्थिक स्थिरता और विकास की संभावनाओं के साथ हम दूसरे देशों में आशा का संचार कर रहे हैं.

मोदी की जाति को लेकर राहुल के बयान पर भाजपा का पलटवार, कहा-

1999 से ही ओबीसी में अधिसूचित

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार राज्यसभा में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में विकास धीमा हुआ था, लेकिन हमने रफ्तार को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पिछड़े वर्गों के लोगों को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती है। इस बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए किया और कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने खुद की जाति को ओबीसी में शामिल किया था। जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच ठन गई है। भाजपा ने उनके दावे को खारिज करते हुए कहा कि गुजरात सूचना आयोग ने 25 जुलाई 1994 को मोध-घांची को ओबीसी के रूप में अधिसूचित किया था। यह वही जाति है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबंधित हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरहरि अमीन ने भी पोस्ट कर राहुल गांधी के दावे को खारिज किया है। उन्होंने अपनी एक्स पर पोस्ट की एक श्रृंखला में कहा कि जब मैं कांग्रेस सरकार में गुजरात के उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत था, तब गुजरात सूचना आयोग ने 25 जुलाई 1994 को मोध-घांची को ओबीसी के रूप में अधिसूचित किया था। यह वही जाति है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबंधित हैं। बाद में गुजरात सूचना आयोग की सिफारिशों पर अमल करते हुए केंद्र सरकार ने साल 1999 में इस जाति को ओबीसी में शामिल कर

लिया था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में ओबीसी का दर्जा पहली बार साल 1992 में तब लागू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने उस साल इंदिरा साहनी फैसले में 1990 में जारी सरकारी आदेश को बरकरार रखा था। 1990 में जारी आदेश में कहा गया था कि जाति पिछड़ेपन का एक स्वीकार्य संकेतक है। अतः वर्ष 1992 से पहले किसी भी जाति को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया जाना संभव नहीं था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर मूर्खतापूर्ण झूठ फैलाकर ओबीसी समुदायों का अपमान कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि वे तुरंत अपना झूठ वापस लें। उन्हें ओबीसी को बदनाम करना बंद करना चाहिए।

वहीं, पीएम मोदी की जाति को लेकर राहुल गांधी के बयान पर अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी प्रतिक्रिया दी है। आयोग ने कहा कि ओबीसी समाज के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी के बयानों से नाराज हैं। इसी के साथ आयोग ने कहा कि ओबीसी समुदाय के प्रति राहुल के मन में जो नफरत है वो उन्हें स्पष्ट रूप से अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। संसद के पटल पर प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के आरक्षण विरोधी रवैये को उजागर किया। आयोग ने कहा कि मंडल आयोग के विरोध में संसद में राजीव गांधी की टिप्पणियों के बारे में तो सभी जानते हैं। आज राहुल गांधी करोड़ों पिछड़े वर्ग के लोगों को अपमानित कर रहे हैं और विभाजन के बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं।

वित्त मंत्री आज पेश करेंगे बजट

रायपुर. छत्तीसगढ़ में विधानसभा का पहला बजट सत्र शुरू हो चुका है. ये एक मार्च तक चलेगा. इस दौरान प्रदेश की जनता के लिए विष्णुदेव साय की सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी. 9 फरवरी को प्रदेश के वित्त मंत्री ओम प्रकाश चौधरी बजट पेश करेंगे. बजट को लेकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर के लोगों को काफी उम्मीदें हैं. खासकर इलाके के आदिवासी छात्र सरकार से काफी आस लगाए हुए हैं. बस्तर के आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ रोजगार को लेकर इस बजट से कई उम्मीदें हैं. आदिवासी छात्रों का कहना है कि राज्य गठन के 23 साल पूरे होने के बाद आज भी शिक्षा के क्षेत्र में बस्तर काफी पिछड़ा हुआ है. संसाधनों की कमी

और तकनीकी शिक्षा नहीं मिल पाने की वजह से बाकी संभाग के मुकाबले बस्तर संभाग के छात्र शिक्षा में काफी पिछड़े हुए हैं. आदिवासी छात्रों का कहना है कि स्कूली शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा में भी शिक्षकों की भारी कमी है, जो बस्तर में शिक्षा में पिछड़ने की सबसे प्रमुख वजह है. ऐसे में छात्रों को उम्मीद है कि इस बार राज्य सरकार की आम बजट में खास तौर से शिक्षा पर फोकस किया जाएगा. ज्यादातर छात्र आस लगाए हैं कि इस बार राज्य में और खासकर बस्तर संभाग में ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती होगी. वहीं बस्तर के ग्रामीण इलाकों के छात्रों का कहना है कि पिछली सरकार ने केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई को निःशुल्क करने की बात कही थी. नई सरकार से भी यही उम्मीद है कि वह मेडिकल पढ़ाई के लिए फीस को कम कर दे, ताकि गरीब परिवार के बच्चे भी मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बन सकें.

वट वृक्ष हमारा रजिस्टर्ड सिम्बल: शरद

मुंबई। महाराष्ट्र में शरद पवार गुट को अब नया नाम और चुनाव चिन्ह मिल गया है. चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को पार्टी के नए नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार को मंजूरी दे दी थी. शरद गुट का चुनाव चिन्ह पेड़ है, जिसे लेकर अब विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताई है. विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने शरद गुट को नई पार्टी के चुनाव चिन्ह पेड़ को लेकर आपत्ति जताई है. वीएचपी का कहना है कि बरगद का पेड़ उनके संगठन का पंजीकृत प्रतीक है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को नई

पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न तय करने के लिए विकल्प सुझाने के लिए बुधवार शाम तक की समयसीमा दी थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के लिए नए नाम पेश किए, जिनमें से एक को चुना जाएगा।

चुनाव आयोग ने इससे पहले शरद पवार गुट को झटका देते हुए अजित गुट को असली एनसीपी करार दिया। आयोग ने कहा था कि सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए अजित गुट ही असली एनसीपी है। चुनाव आयोग के इस फैसले से अजित पवार गुट को एनसीपी के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने का अधिकार मिल गया। आयोग ने सभी दस्तावेजी सबूतों का विश्लेषण करने के बाद कहा था कि यह स्पष्ट है कि अजीत के समूह का पार्टी के अलावा पार्टी और संगठन पर भी प्रभुत्व है। उनके रूप के और भी लोग हैं। इस वजह से पार्टी का नाम और सिंबल दोनों अजित गुट को दिया गया है।

शरद पवार बनाम अजित पवार गुट मामले में चुनाव आयोग ने 147 पेज का आदेश दिया है। इस क्रम में आयोग ने दोनों समूहों के सभी बिंदुओं और साक्ष्यों का विश्लेषण किया है। आयोग ने सभी दस्तावेजी सबूतों का विश्लेषण किया है और कहा है कि यह स्पष्ट है कि अजीत के समूह का पार्टी के अलावा पार्टी

पवार गुट के नए चुनाव चिह्न पर विश्व हिंदू परिषद की आपत्ति

और संगठन पर भी प्रभुत्व है। उनके रूप के और भी लोग हैं। इस वजह से पार्टी का नाम और सिंबल दोनों अजित गुट को दिया गया है। महाराष्ट्र से छह राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव के मद्देनजर शरद पवार गुट को चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 39 का पालन करने के लिए विशेष छूट दी गई। उनसे बुधवार शाम 4 बजे तक नई पार्टी बनाने के लिए तीन नाम देने को कहा गया है।

प्रमुख समाचार

इमरान समर्थित उम्मीदवार 125 सीटों पर आगे, दूसरे नंबर पर शरीफ

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की 336 सीटों और चार प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव हो रहा है. ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है, जब देश आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है. इमरान खान की पीटीआई125 सीटों पर आगे चल रही है. वहीं, नवाज शरीफ की पार्टी 44 सीटों पर आगे है, जबकि बिलावल भुट्टो की पार्टी तीसरे नंबर पर चल रही है. वहीं, नवाज शरीफ खुद लाहौर सीट से पीछे है. पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में मोबाइल फोन सेवाएं आंशिक रूप से बहाल कर दी गई हैं. इस बात की जानकारी गृह मंत्रालय ने दी. पाकिस्तान चुनाव आयोग के प्रवक्ता हारून शिनवारी ने कहा है कि चुनाव के नतीजे समय पर घोषित किए जाएंगे. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इंटरनेट आउटेज से इलेक्ट्रॉन वाचडॉग सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा. पाकिस्तान में चुनाव संपन्न होने के बाद वोटिंग जारी है. डॉन ने रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि जो वोटर्स मतदान केंद्र बंद होने के समय से पहले परिसर में मौजूद थे, उन्हें चुनावी प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी गई है. पूरे पाकिस्तान में धांधली के आरोपों और इंटरनेट ठप होने की घटनाओं के बीच मतदान संपन्न हो गया है. मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे तक जारी रही.

सुको का सिख फॉर जस्टिस के समर्थक को जमानत देने से इंकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सिख फॉर जस्टिस के कथित सदस्य को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया एक आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के संकेत देते हैं। सुनवाई कर रही पीठ ने एनआईए द्वारा जांच किए गए

यूएपीए मामले में गुरविंदर सिंह उर्फ गुरप्रीत सिंह गोपी को जमानत देने से इनकार करने वाले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। 10 जुलाई, 2019 को गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा बनाए गए खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए केंद्र द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। एक साल बाद एक जुलाई, 2020 को केंद्र ने यूएपीए के प्रावधानों के तहत पन्नू को आतंकवादी के रूप में नामित किया। गुरविंदर सिंह पन्नू सहित कई अन्य लोगों पर एनआईए द्वारा 2020 में आईपीसी, शस्त्र अधिनियम और यूएपीए के तहत विभिन्न अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था।

हल्द्वानी में उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश

नई दिल्ली। हल्द्वानी में अवैध मस्जिद-मजार के ध्वस्त होने के बाद बवाल हुआ और इस दौरान आगजनी भी हुई. वहीं इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और उपद्रवियों को गोली मारने का आदेश दिया है. बिगड़ते हालात को देखते हुए

उत्तराखंड सरकार ने हल्द्वानी में कर्फ्यू घोषित कर दिया है और इसके साथ ही दंगा करने वालों के खिलाफ यूएपीए के अंतर्गत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. वहीं सीएम धामी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ हालात की समीक्षा की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. उत्तराखंड सरकार ने घटना के बाद इलाक में पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई है. वहीं खंड शिक्षा अधिकारी हल्द्वानी हरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि हल्द्वानी के समस्त प्रकार के कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालय को सुरक्षात्मक कारणों से अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे. समस्त प्रकार के विद्यालय उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगे. धामी ने कहा कि न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी.

उद्धव गुट के नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या

मुंबई। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या के बाद सियासी पारा गरमा गया है. शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने इस घटना पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र

फड़नवीस के इस्तीफे की मांग की है. शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में गुंडों का राज है. उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम गैंगस्टर्स से मिलते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि राज्य गैंगस्टर्स के हाथ में है. इसलिए कानून का डर नहीं बल्कि पुलिस को शिंदे गैंग की सेवा में छोड़ दिया गया है. आरोपी मॉरिस भाई ने पहले अभिषेक के साथ फेसबुक लाइव किया और उसके बाद गोली मारी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. नेताओं सहित कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया. लेकिन ये वीडियो इतना विभत्स है कि एबीपी लाइव उसे दिखा नहीं सकता. संजय राउत ने कहा, अभिषेक घोसालकर पर गोली चलाना चौंकाने वाला है. गृह मंत्री फडणवीस चाय-पान पर चर्चा करते घूम रहे हैं. देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दें!

रेलवे की 6 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

नई दिल्ली। रेलवे ट्रैक्स पर कंजेशन को दूर करने के साथ ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमिटी की बैठक में भारतीय रेलवे की छह मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है. इन मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स के जरिए रेलवे ट्रैक पर रेल यात्रा को सुगम बनाने में मदद मिलेगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी, ऑयल इंपोर्ट कम होगा साथ ही प्रदूषण पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी. पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीईए की बैठक हुई. इस बैठक में रेल मंत्रालय के 6 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है जिसपर 12,343 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इन प्रोजेक्ट्स की पूरी फंडिंग केंद्र सरकार करेगी. भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त सेक्शन पर मल्टी ट्रैकिंग प्रस्ताव के जरिए रेलवे ट्रैक्स पर कंजेशन को घटाने के साथ ऑपरेशन को बेहतर करने में मदद मिलेगी. सरकार ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि ये 6 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स 6 राज्यों राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नागालैंड के 18 जिलों को कवर करेगा जिससे रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 1020 किलोमीटर का इजाफा होगा और 3 करोड़ मैन-डेज के बराबर इन राज्यों के लोगों को रोजगार मिल सकेगा. मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत इन प्रोजेक्ट्स को तैयार किया जाएगा.

मोदी के आत्मविश्वास से विपक्षी खेमे में काफी बेचैनी दिखाई दे रही है

डॉ. आशीष वशिष्ठ

प्रधानमंत्री मोदी ने गत 5 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण देते हुए कहा कि हमारा तीसरा कार्यकाल 1,000 सालों की नींव रखने का काम करेगा और उसमें बहुत बड़े फैसले होंगे। बीती 2 फरवरी को 'इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो' के उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल की योजनाओं के बारे में बताया। जैसे ही पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल की बात की तो लोग लगातार तालियां बजाने लगे। इसके बाद पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा के समझदार को इशारा ही काफी होता है।

26 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में नए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर अपने भाषण में कहा कि, मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी के चेहरे और भाषणों में झलकता आत्मविश्वास विपक्ष की बेचैनी का बड़ा कारण है।

बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर ऐलान किया कि अगले साल वे फिर लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे और अपनी उपलब्धियों का ब्योरा पेश करेंगे। लेकिन यह अहंकार नहीं है। यह बिल्कुल वैसी ही बात है, जैसी बात विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। वास्तव में यह अहंकार का नहीं, बल्कि दोनों तरफ आत्मविश्वास का मामला है। एक तरफ विपक्ष इस आत्मविश्वास से भरा है कि अगले लोकसभा चुनाव में उसकी जीत होगी तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी इस भरोसे में हैं कि वे तीसरी और ऐतिहासिक जीत हासिल कर पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे।

केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में ही नहीं, बल्कि उनकी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी वर्ष में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश अंतरिम बजट से न केवल सरकार का आत्मविश्वास झलकता है कि वह अपने कार्यों के बल पर ही तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी, बल्कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के उसके संकल्प का परिचय भी मिलता है। यह एक ऐसा अंतरिम बजट है, जिसमें सरकार ने चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को रिझाने के लिए कोई लोकलुभावन घोषणा नहीं की। ध्यान रहे 2019 के अंतरिम बजट में कई लोकलुभावन घोषणाएं की गई थीं। इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसका मतलब है कि सरकार मानकर चल रही है कि जनता को उस पर भरोसा है कि वह देशहित में सही दिशा में काम कर रही है। विकास की राजनीति का यह एक नया उदाहरण है। जब सामने लगातार तीसरी पारी की लड़ाई का मैदान सज रहा हो और यह अपेक्षा हो कि लोकलुभावन घोषणाओं का तड़का लगेगा, तब नरेन्द्र मोदी सरकार की ओर से सामाजिक न्याय व समानता के अवसर पैदा करते हुए भविष्य के विकसित भारत का संकल्प दोहराना यह स्पष्ट करता है कि केंद्र में वापसी को लेकर वह विश्वास लबालब है। पीएम मोदी लोकलुभावन घोषणाओं के जरिए नहीं बल्कि अपने दस साल के ट्रैक रिकॉर्ड, जो कहा सो पूरा किया के नारे के साथ ही जनता से समर्थन चाहते हैं।

मोदी-2 की सरकार ने आते ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 की विदाई कर दी। राम मंदिर का रास्ता साफ किया और सीएए, एनआरसी जैसे कानून लेकर आई। मोदी-2 कार्यकाल की विदाई के चार महीने पहले अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले दस वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी की मार से बाहर निकले हैं। ग्रामीण स्तर पर वह सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं जो पहले छोटे शहरों तक में उपलब्ध नहीं थी। बीमारी हर साल पुनः गरीबी के चपेट में आने का बड़ा कारण रहा है लेकिन आयुष्मान योजना ने उस दशा में परिवर्तन ला दिया। सड़क, रेल और हवाई यातायात का परिदृश्य बदल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के कारण रोजगार के भी नए रास्ते खुले हैं। लोगों की औसत आय में 50 फीसद की बढ़ोत्तरी हुई है और सामान्य रूप से यह विमर्श बना है कि देश बदल रहा है, आने वाले समय में दूसरों के लिए पथ प्रदर्शक बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश आत्मविश्वास से भर रहा है और गौरव से भर रहा है। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर सकारात्मकता, आशा, भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपार लोकप्रियता और अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बने माहौल को देखते हुए केंद्र में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनना लगभग तय है। ब्रिटेन के प्रमुख अखबार द गार्जियन में यह संभावना जताने के साथ ही कहा गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जीत ने पार्टी की ताकत को और बढ़ाया ही है। अखबार में ह्ना एलिस पीटरसन की तरफ से लिखे गए कॉलम में कहा गया है कि तीन राज्यों की जीत लोकसभा में भाजपा की संभावनाओं को और मजबूत करने वाली है।

टेटेमड़गु इलाके में पुलिस नक्सली मुठभेड़

■ वायरलेस सेट और नक्सल सामग्री बरामद

सुकमा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार नक्सल गतिविधियों के साथ ही सुरक्षाबलों की गतिविधियां भी तेज गति से बढ़ गई है। लगातार सुकमा जिले में नक्सल घटनाएं घट रही है। एक बार फिर से सुकमा में नक्सली घटना घटी है। जिले के किस्टारम थाना क्षेत्र के टेटेम मड़गु इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है।

सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि किस्टारम थाना क्षेत्र के टेटेममड़गु इलाके में किस्टारम एरिया कमेटी के नक्सलियों के मौजूदगी की सूचना मुखबिर से मिली थी। इस सूचना पर डीआरजी और कोबरा 208 बटालियन की संयुक्त टीम को टार्गेटिंग ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया था। जैसे ही जवान नक्सलियों के चिन्हित इलाके में पहुंचे। नक्सलियों ने जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जिसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में जवानों को भारी पड़ता देख नक्सलियों घने जंगलों की आड़ लेकर फरार होने में कामयाब रहे। जिसके बाद जवानों ने घटना स्थल में सर्चिंग अभियान चलाया। सर्चिंग के दौरान मौके पर से नक्सलियों का एक वायरलेस सेट व भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद किया गया।

फिलहाल इलाके में जवानों का सर्चिंग अभियान जारी है।

पुलिस ने 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार

नारायणपुर। तीन सशस्त्र नक्सलियों को नारायणपुर पुलिस ने पकड़ा है। तीनों नक्सली कुतूल एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य थे। डीआरजी और एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। पकड़े गए नक्सलियों के कब्जे से बंदूक और विस्फोटक सामग्री जब्त की है।

हथियार लूटने की नीयत से जवानों पर की फायरिंग नारायणपुर पुलिस नक्सल विरोधी अभियान संचालित कर रही है। इसी के तहत 5 फरवरी को बेड़ामामेटा जंगल में सर्चिंग के लिए गए जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। जिसके बाद नक्सली जंगल की आड़ में फरार हो गए। सर्चिंग के दौरान जवानों को जंगल में तीन संदिग्ध लोग मिले। उनसे पूछताछ और उनके सामान की तलाशी लेने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पता चला कि पकड़े गए तीनों कुतूल एरिया कमेटी में सक्रिए नक्सली के रूप में पिछले कई सालों से काम कर रहे थे।

तीनों नक्सली भेजे गए जेल नारायणपुर एएसपी हेमसागर सिदार ने बताया तीनों नक्सली रानू पोड़ियाम निवासी बेड़ामामेटा 2। सुधराम मण्डावी निवासी कट्टाकाल और विजय पोडियाम निवासी बेड़ामामेटा के रहने वाले हैं। उनके कब्जे से 3 भरमार बंदूक, डेटोनेटर, बैटरी, बिजली वायर और दैनिक उपयोग का सामान मिला है। नक्सलियों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 120(बी), 307 , 25, 27 आर्म्स एक्ट , 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

मुठभेड़ में आठ लाख का इनामी नक्सली चन्द्रन्ना मारा गया

दंतेवाड़ा। सुकमा-दंतेवाड़ा सीमा पर बुधवार शाम लगभग 5 बजे हुई मुठभेड़ में जवानों ने 8 लाख के इनामी नक्सली चन्द्रन्ना उर्फ सत्यम को ढेर कर दिया है वह गरगुंडा एरिया कमेटी में सक्रिय था। पुलिस ने मौके से शव, हथियार सहित अन्य नक्सल सामग्री बरामद किया है। एसपी दंतेवाड़ा गौरव राय ने मुठभेड़ की पुष्टि की है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि गोंदपल्ली, परलागट्टा और बड़ेपल्ली गांव के जंगल में बड़ी संख्या में हथियारबंद नक्सली मौजूद हैं। मुखबिर की सूचना पर दंतेवाड़ा से डीआरजी, सीआरपीएफ और बस्तर फाइटर की संयुक्त टुकड़ी बुधवार की सुबह मौके के लिए रवाना किया गया। शाम लगभग 5 बजे नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए, मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान एक नक्सली का शव बरामद किया गया जिसकी शिनाख्त चन्द्रन्ना उर्फ सत्यम के रूप में की गई है। इस पर 8 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था और कई नक्सली वारदातों में शामिल रहा है। वह 2013 के पूर्व माड़ डिवीजन का डीवीसी सदस्य था। कुछ वर्षों से दक्षिण बस्तर डिविजन के जगरगुंडा एरिया कमेटी में सक्रिय था।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मारे गए नक्सली चन्द्रन्ना उर्फ सत्यम के खिलाफ जिला नारायणपुर में निम्न अपराध दर्ज है - थाना सोनपुर, जिला नारायणपुर अपराध क्रमांक 01/2024 धारा- 147,148,149,307 आईपीसी. 25, 27 आर्म्स एक्ट 10, 13(1), 20, 23, 38(2), 39(2) वि.वि.क्रि.क.नि. अधिनियम के तहत अपराध पंजिबद्ध है। थाना सोनपुर, जिला नारायणपुर अपराध क्रमांक 02/2021 धारा- 147,148,149, 307, आईपीसी 25, 27 आर्म्स एक्ट, 4,5 विस्फोटक पदार्थ अधि.13(1), 20, 38(1)(2) 39(1) विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारवा अधिनियम जोडऩा धारा 302 भादवि के तहत अपराध पंजिबद्ध है। थाना नारायणपुर जिला नारायणपुर अपराध क्रमांक नारायवापुर 69/11 धारा 307 147 148 149 आईपीसी, 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजिबद्ध है। थाना धौड़ाई, जिला नारायणपुर अपराध क्रमांक 05/10 धारा 307 147 148 149 121क 122 302 397आईपीसी 25,27 आर्म्स एक्ट 13,38(2) विविक्रिक के तहत अपराध पंजिबद्ध है।

नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ विकास होगी प्राथमिकता -जितेंद्र यादव

बीजापुर। नवनियुक्त बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने पदभार ग्रहण करने के बाद गुरूवार को पत्रवार्ता के दौरान उन्होने कहा कि बीजापुर नक्सल प्रभावित जिला होने के कारण काफी चुनौती भरा जिला है, यहां कि परिस्थिति मैदानी जिलों से एक दम अलग है। इसके बावजूद नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ-साथ जिले का विकास मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जिले में पुलिस विभाग के सारे कार्य पारदर्शिता से किया जायेगा जिससे किसी प्रकार कि असमंजस कि स्थिति निर्मित ना हो सके। मिडिया कर्मियों ने अवैध नशा पर रोक लगाने के साथ यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ का आग्रह किया, जिस पर एसपी ने गंभीरता पूर्वक कार्य करने का आश्वासन भी दिया। विदित हो कि जितेंद्र यादव 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान बलौदाबाजार, कांकेर और दुर्ग जिले में एडिशनल एसपी के रूप में कार्य करने के पश्चात बालौद जिले के एसपी के रूप में एक वर्ष आठ माह अपनी सेवा प्रदान किया। जिसके बाद राज्य शासन ने उन्हें बीजापुर जिले के एसपी का दायित्व सौंपा हैं।

हाथी से फसल बर्बाद अब मुआवजा के लिए लंबा इंतजार

कोरबा। हाथी और मानव के बीच द्वंद लगातार जारी है। हाथी प्रभावित क्षेत्र के अन्नदाता हाथियों के उत्पात से बुरी तरह से जूझ रहे हैं। जंगल घटने से हाथी रिहायशी इलाकों की तरफ कूच करते हैं। दाना और पानी के लिए वह खेत में घुस आते हैं। जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। मैदानी क्षेत्र के किसानों ने अपना धान समर्थन मूल्य पर बेचा और उन्हें इसके दाम भी मिल गए लेकिन कटघोरा मंडल के हाथी प्रभावित क्षेत्र के किसानों के धान की खड़ी फसल को हाथियों ने बर्बाद कर दिया। उन्हें पिछले 5 महीनो से नुकसान के मुआवजे का इंतजार है। जिसे लेकर वह खासे परेशान हैं।

डेढ़ सौ किसानों की फसल बर्बाद

ग्राम पंचायत हरदेवा के पंच सिरपत सिंह मरकाम ने बताया कि हाथियों ने गांव में जमकर उत्पात मचाया है। जिससे लगभग डेढ़ सौ किसान प्रभावित हुए हैं। कई किसानों के घर को भी हाथियों ने तोड़ दिया है। आए दिन हाथी खेतों में आ जाते हैं। जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। पिछले साल अक्टूबर माह में फसल और मकान की क्षतिपूर्ति के लिए वन विभाग ने गांव का दौरा किया था। किसानों से जानकारी लेकर प्रकरण भी तैयार किया, लेकिन अब तक

किसी भी तरह का मुआवजा किसानों को नहीं मिला है।

किसान बृजलाल ने कहा हमारा लगभग 19 एकड़ रकबा खेत है। जिसमें हमने धान की बुवाई की थी। हाथियों ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। 20 हजार के तो बीज ही लग गए थे। अब हमारे सामने रोजी रोटी का संकट है। बीटगार्ड ने गांव में आकर कहा था कि मुआवजा मिलेगा। खेत में खड़े करके हमारी फोटो भी खींची गई लेकिन मुआवजा नहीं मिला है। आसपास के क्षेत्र के किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान भी बेच दिया, लेकिन हमें मुआवजा भी नसीब नहीं हो रहा है।

महीनों बीत गए, नहीं मिला मुआवजा

हाथियों के द्वारा फसल नुकसानी के संबंध में कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत हरदेवा के किसानों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। किसानों ने कलेक्टर को लिखित आवेदन दे पेश किया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि हाथियों ने फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जिससे किसान आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। खेतों में जाकर वन विभाग के मैदानी अमले ने मुआवजा प्रकरण भी तैयार किया। किसानों के फोटो खींचे लेकिन क्षति पूर्ति की राशि महीनो बीत जाने के बाद भी नहीं मिली है।

कटघोरा वन मंडल से जानकारी मिली है कि किसानों के फसल नुकसानी का प्रकरण तैयार किया गया है। मुआवजा बांटने की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी।

अस्पताल प्रबंधन व डॉक्टर देंगे 8 लाख की क्षतिपूर्ति

जगदलपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक प्रकरण में अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर को ऑपरेशन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर एमपीएम अस्पताल जगदलपुर और डॉ. सरिता थॉमस के खिलाफ बुधवार को पारित आदेश में चार-चार लाख रुपए की क्षतिपूर्ति और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना अदा करने का आदेश पारित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि जगदलपुर निवासी रजनी जैन की एक आंख में कम दिखने की शिकायत होने पर उसने एमपीएम अस्पताल में डॉ. सरिता थॉमस से अपनी आंख की जांच करवाई थी। तब डॉक्टर द्वारा उसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने की सलाह दी गई थी। डॉक्टर की सलाह पर आवेदिका ने एमपीएम अस्पताल में अपनी आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था। आपरेशन के दूसरे दिन से ही उसकी आंख से दिखना पूरी तरह बंद हो गया था। इस संबंध में रजनी जैन द्वारा डॉक्टर से शिकायत की गई थी। एक सप्ताह बाद पुन: डॉक्टर को दिखाने पर भी उसकी आंखों से दिखना आरंभ नहीं हुआ। आवेदिका रजनी जैन ने विशाखापट्टनम स्थित नेत्र चिकित्सालय में अपनी आंख की जांच करवाई तो वहां बताया गया था कि उसकी आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन गलत होने के कारण बांई आंख की रोशनी चली गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व महाधिवक्ता की फीस बकाया

जुगल किशोर गिल्डा ने हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा

बिलासपुर। बीजेपी के रमन शासन में शासकीय मामलों की पैरवी करने वाले महाधिवक्ता जुगल किशोर गिल्डा ने हाईकोर्ट में कोर्ट बकाया फीस को लेकर याचिका लगाई है।इस याचिका में गिल्डा ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्हें रमन सरकार में महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था।जिसमें रमन सरकार के पक्ष में गिल्डा ने हाईकोर्ट समेत सुप्रीम कोर्ट तक शासन के मामलों की पैरवी की थी।लेकिन राज्य शासन ने उस समय गिल्डा को हाईकोर्ट के मामलों की फीस तो दी।लेकिन सुप्रीम कोर्ट में की गई पैरवी की फीस नहीं दी।जो तकरीबन एक करोड़ दस लाख के आसपास है।जिसके भुगतान के लिए अब जुगल किशोर गिल्डा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच में सुनवाई की गई।

डॉ रमन सिंह की बीजेपी सरकार में हाई कोर्ट में नागपुर के अधिवक्ता जुगल किशोर गिल्डा को महाधिवक्ता बनाया गया था। वह काफी तेज तर्रार वकील रहे हैं। यही वजह रही कि रमन सिंह सरकार में की गई पैरवी में सरकार ने कई मामलों में जीत हासिल की।लेकिन रमन सरकार को कोर्ट में जीत दिलाने वाले जुगल किशोर गिल्डा खुद न्यायालय की शरण में हैं।

जुगल किशोर गिल्डा ने 23 जनवरी 2014 को महाधिवक्ता का पदभार ग्रहण किया था। उसके पूर्व गिल्डा जून 2006 से अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर थे। जुगल किशोर गिल्डा ने महाधिवक्ता रहते सर्वाधिक 94व मामलों में सफलता हासिल की थी। 2018 में राज्य में सरकार बदलने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने लगे। गिल्डा ने लंबे समय तक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की हैं।जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की ओर से पैरवी की है।

गिल्डा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में की गई पैरवी की फीस उन्हें नहीं मिली है।वहीं इस मामले में सीएसआईडीसी की ओर से कहा गया कि पूर्व महाधिवक्ता गिल्डा को सरकार ने नियुक्त नहीं किया था। जिस पर गिल्डा के वकील ने कहा कि वह सरकार की ओर से महाधिवक्ता नियुक्त थे। ऐसे में उन्हें अलग से नियुक्त करने का सवाल ही नहीं उठाता है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी तय की गई है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

महिला नक्सली के साथ 2 ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान पूना नर्कोम-नई सुबह-नई शुरुआत के तहत नक्सली संगठन में सक्रिय 1 लाख की ईनामी महिला नक्सली पोडियामी राजे (केएएमएस अध्यक्ष) एवं कवासी भोला (मिलिशिया सदस्य) निवासी थाना चिंतागुफा ने नक्सल ऑपरेशन कार्यालय सुकमा में उत्तम प्रताप सिंह, उप पुलिस अधीक्षक सुकमा एवं वरूण राज, सहायक कमाण्डेन्ट 50 वाहिनी सीआरपीएफ के समक्ष गुरूवार को आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पित दोनों नक्सलियों को शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत सहायता राशि व अन्य सुविधाऐं प्रदाय किया जायेगा। नक्सलियों को आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित कराने में आरएफटी कोन्टा रेंज व 50, 228 वाहिनी सीआपीएफ का योगदान रहा।

कांकेर में तकनीकी शिक्षा का हाल-बेहाल

कांकेर। कांकेर में तकनीकी शिक्षा का हाल बेहाल है। दरअसल, जिले के नरहरपुर विकासखण्ड में साल 2014 में क्षेत्र के छात्रों के तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(आईटीआई) कॉलेज खोला गया था। ताकि छात्र यहां से इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य औद्योगिक ट्रेडों में तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकें। सरकार ने यह आईटीआई कॉलेज तो खोला लेकिन इस कॉलेज में प्रैक्टिकल समान देना ही भूल गए। आलम यह है कि पिछले 9 साल से बिना प्रेक्टिकल समान के छात्र यहां पढाई कर रहे हैं। जिले के आईटीआई के छात्र गुरुवार को कांकेर कलेक्टर से फरियाद लेकर पहुंचे थे। इस दौरान ईटीवी भारत ने छात्रों से बातचीत की। बातचीत के दौरान बच्चों ने अपनी परेशानियों पर खुलकर बात की। आईटीआई के एक स्टूडेंट् ने बताया कि, आईटीआई 2014-15 में खुला था। प्रैक्टिकल सामान की बहुत ज्यादा जरूरत होती है बिना प्रैक्टिकल के हमारी पूरी आईटीआई की पढ़ाई ही अधूरी है।

भिलाई में आवारा डॉग्स का खौफ, अस्पताल में बढ़े मामले

भिलाई। भिलाई में ऐसा कोई मोहल्ला या गली नहीं है जहां आवारा डॉग्स ना हों। शहर की सड़कों से लेकर छोटे से छोटे गली मोहल्ले में इनका आतंक है। रोजाना भिलाई टाउन में कहीं ना कहीं डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद भी जिम्मेदार नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा।जानकारी के अनुसार क्षेत्र में लगभग सैकड़ों की संख्या में आवारा डॉग्स हैं। जिन पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। आवारा डॉग्स के कारण शहरवासी के साथ राहगीर भी परेशान हो रहे हैं। वाहनों का पीछा करते समय ये आवारा डॉग्स किसी को भी अपना शिकार बना लेते हैं। कई बार डर के कारण दोपहिया वाहन चालक हादसे का शिकार बनते हैं। शहर के कई कॉलोनियों में परेशान होकर लोग सुबह और देर रात घरों से निकलने में कतराने लगे हैं। वैशाली नगर के ईडब्ल्यूएस मकान और कालीबाड़ी के बीच सीधी सड़क उप स्वास्थ्य केंद्र वैशाली नगर की ओर जाती है। इस सड़क में रात 10 बजे के बाद आवागमन करना मुश्किल हो जाता है। आवारा डॉग्स दो पहिया वाहन चालकों को देखते ही दौड़ाने लगते हैं।

अवैध नशीली दवाइयों के साथ 3 गिरफ्तार

जगदलपुर। थाना सिटी कोतवाली को दो अलग-अलग सूचना प्राप्त हुआ कि 3 व्यक्ति जो लुक छिपकर अवैध नशीली गोली दवाई शहर में बिक्री कर रहे है। दलपत सागर तथा मंगडू कचौरा के पास से क्रमश: दोनो नशीली दवाई तथा नशीली सीरप बेच रहे है कि सूचना पर हनुमान मंदिर दलपत सागर तथा मांगडू कचौरा चौक के पास से आरोपी प्रतीक ठाकुर, विवेकदास मानिकपुरी और अजय राजपूत को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध नशीली दवाई टेबलेट 4 पैकेट के अंदर 2850 नग, टैबलेट 355 नग कुल 3,205 नग नशीली टैबलेट्स तथा घटना स्थल मंगडू कचौरा से कोडीन युक्त सीरप 59 नग को बरामद किया गया, जो अवैध एवं प्रतिबंधित नशीली दवा की श्रेणी में आता है। इस प्रकार दोनों जगहों से 3,205 नग टैबलेट्स, 59 नग कोडीन युक्त सीरप, 3 मोबाइल, एक मोटरसाइकिल, 3 नग धारदार चाकू, नगद 525 रूपये को बरामद कर आरोपियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियो को गुरूवार को न्यायालय रवाना किया गया।

विधायक देवेन्द्र यादव ने सदन से मांगा अवकाश

भिलाई। भिलाई के कांग्रेस के विधायक देवेन्द्र यादव की अवकाश आवेदन पर स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने लंबित रखा है। देवेन्द्र ने कल अपने आवेदन में अपरिहार्य कारणों से बजट सत्र के लिए अनुपस्थिति मंजूर करने का आग्रह किया था। स्पीकर डॉ. सिंह ने आज सदन में उनका आवेदन पढ़ा। डॉ. सिंह ने कहा कि देवेन्द्र हमारे सदन के सदस्य हैं। उन्होंने अपरिहार्य कारणों से अवकाश मांगा है। संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर ने इस पर आपत्ति ली। उन्होंने आवेदन में अपरिहार्य कारण को अपर्याप्त बताते हुए सदन में उपस्थिति की व्यवस्था देने का आग्रह किया। अध्यक्ष डॉ. सिंह ने इस आपत्ति को ध्यान में रखते हुए अवकाश आवेदन पर आने वाले दिनों में व्यवस्था देने की बात कही। बता दें कि देवेन्द्र यादव बजट सत्र के पहले दिन से सदन में नहीं आ रहे हैं। देवेन्द्र कांग्रेस शासनकाल में हुए कोल घोटाले में ईडी के आरोपी हैं और दो बार जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद से फरार हैं।

हम होंगे कामयाब सेशन में बच्चों ने भगाया एग्जाम का डर

■ बच्चों ने जाना सफलता का मंत्र

कवर्धा। कबीरधाम जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से हम होंगे कामयाब कैंपेन का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति को समझने और पढ़ाई के दौरान तनाव मुक्त रहने के टिप्स बताना था। यूनिसेफ के सहयोग एवं जिला प्रशासन के माध्यम से हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने जिले के 50 से अधिक शासकीय हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों के विद्यार्थियों से चर्चा की।

आईपीएस ने दिए सफलता के टिप्स

पुलिस अधीक्षक ने छात्रों को बताया कि परीक्षा के पहले कैसे तैयारी करनी है। परीक्षा से डरने की जरुरत नहीं है।परीक्षा से

आप लोग हर समय गुजरेंगे। इसलिए अपनी तैयारी को पूरी रखे। यदि चिंता होती है तो अपने साथी, शिक्षक या अपने माता-पिता , भाई बहन को जरुर बताएं। इस दौरान 10वीं और 12 वीं कक्षा के विद्यार्थी जो परीक्षा देने वाले हैं।उन्होंने ध्यान से आईपीएस डॉ।अभिषेक पल्लव की बातों को सुना और उनसे सवाल भी पूछे।

छात्रों ने पूछे सवाल

इस दौरान विद्यार्थियों ने एसपी अभिषेक पल्लव से कई तरह के सवाल भी पूछे। जैसे पढ़ते-पढ़ते नींद आ जाती है, पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। माता पिता का अंकों को लेकर दवाब रहता है। अभी एक महीने बचा है तो किस प्रकार से तैयारी करनी है।जिस पर एसपी ने बच्चों को बहुत ही अच्छे तरिके से इसके जवाब दिए।

एसपी डॉ अभिषेक पल्लव ने कहा जो बच्चों के सवाल थे उनका जवाब दिया गया। कैसे स्ट्रेस को ठीक करें। कैसे पढ़ा जाए। कैसे सिलेबस को पूरा किया जाए। एग्जाम के दौरान कैसी तैयारी की जाए।उम्मीद है कि ऑनलाइन सेशंस का बच्चों को फायदा होगा। बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे,तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाएंगे।

डिप्रेशन में जाने वाले बच्चों को दी सीख

एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि दसवीं और बारहवीं के बोर्ड एग्जाम हैं। दसवीं के बच्चे पहली बार बोर्ड एग्जाम देते हैं। देखा गया है कि बच्चे काफी चिंतित रहते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं। काफी लोग एग्जाम स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन में आकर बहुत से बच्चे रिज्लट से पहले या रिज्लट के बाद सुसाइड भी कर लेते हैं। इसलिए ऑनलाइन के माध्यम से जिले लगभग 50 शासकीय स्कूलों के बच्चों से जुड़ा गया। उनसे बातचीत की गई। इससे उनको फायदा मिला।

बलरामपुर धान खरीदी में 3 करोड़ से ज्यादा का घपला, प्रभारी तहसीलदार निलंबित

बलरामपुर। जिले के रामानुजगंज में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान करोड़ों का खेल खेला गया। धान खरीदी में अनियमितता करते हुए प्रभारी तहसीलदार ने सरकार को साढ़े 3 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया। जिसके बाद प्रभारी तहसीलदार विष्णु गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

रामानुजगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत कुछ समितियों में अपंजीकृत किसानों के द्वारा अन्य लोगों के रकबे में अवैध तरीके से तहसीलदार की मिलीभगत से मंडी में धान बेचने का खुलासा हुआ। जिसमें 3 करोड़ 63 हजार रुपये से ज्यादा के भ्रष्टाचार की बात सामने आई। मीडिया और समाचार पत्रों में इस खुलासे के बाद सरगुजा कमिश्नर में मामले की जांच बैठाई। जांच में प्रभारी तहसीलदार विष्णु गुप्ता की संलिप्तता सामने आई। जिसके बाद सरगुजा कमिश्नर ने प्रभारी तहसीलदार के निलंबन का आदेश जारी किया।

आदेश की कॉपी में ये उल्लेख किया गया है कि प्रभारी तहसीलदार विष्णु गुप्ता द्वारा सिविल सेवा आचरण अधिनियम के खिलाफ काम करने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक निलंबन के दौरान सुरजपुर जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में अटैच कर दिया गया है।

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 1 फरवरी तक बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 1 नवम्बर 2023 से धान खरीदी शुरू हुई। जिले में धान खरीदी के लिए 49 धान उपार्जन केन्द्र बनाये गये हैं। 1 फरवरी तक जिले में 41081 किसानों से कुल 2574870 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। उस तारीख तक 1690030 क्विंटल धान मिलर्स ने मिलिंग के धान का उठाव कर लिया है।

मछली ही नहीं, मगरमच्छ भी होगा तो जरूर पकड़ा जाएगा : उप मुख्यमंत्री

■ **महादेव एप मामला सदन में गूंजा, राजेश मूणत ने अफसरों को बचाने का लगाया आरोप**

रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र में महादेव सट्टा एप का मामला गूंजा। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने महादेव एप का मामला उठाते हुए संलिप्त अफसरों को बचाने का आरोप लगाया। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भरोसा दिलाया कि मछली ही नहीं अगर मगरमच्छ भी होगा तो जरूर पकड़ा जाएगा।

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने सदन में मुद्दा उठाते हुए कहा कि महादेव एप के नाम से राज्य में एक गोरखधंधा चला। राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग इनवॉल्व हैं। यह संवेदनशील मुद्दा है। वैशालीनगर विधानसभा से ही करीब बीस हजार युवा महादेव सट्टा से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि करीब 90 केस दर्ज किए गए हैं। सरकार, जिस पर सुरक्षा की ज़िम्मेदारी है। उसी सरकार ने गिरोहबंदी कर योजनाबद्ध तरीक़े से युवाओं को इस अवैध काम में झोंक दिया। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि मामले में किन-किन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई?

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस मामले की जांच जारी है। जांच और बयान के आधार पर किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता। तथ्य प्रमाणित होने के बाद विष्णुदेव सरकार कार्रवाई करने में एक घंटा भी नहीं लगाएगी। इस मामले में जो भी दोषी होगा चाहे वह किसी भी दल का क्यों ना हो सब पर कार्रवाई होगी। इस प्रकरण में यह बात सामने आई थी कि चार्टर प्लेन से जिन्हें शादी में दुबई ले ज़ाया गया था, उनका भी डिटेल्स हम निकलवा रहे हैं। सबसे पूछताछ होगी।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नौजवान जो राह से भटके हुए हैं, ऐसे युवा महादेव सट्टा एप से जुड़कर अपनी बर्बादी का रास्ता चुन लिया। अब तक 90 एफआईआर दर्ज हुई है। 67 प्रकरणों में से 54 पर चालान पेश हो गया है। दुबई में रह रहे छत्तीसगढ़ के लोग ही इसका संचालन कर रहे हैं। लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है। रेड कॉर्नर नोटिस दिया गया है। प्रत्यर्पण के लिए प्रयास चल रहा है।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि महादेव एप से जुड़े बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है। जिन अधिकारियों की भूमिका पाई गई है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। दो जेल में हैं। कुछ सस्पेंड हैं। राजेश मूणत युवा मोर्चा से हैं, और मैं भी युवा मोर्चा से हूँ। जो आग उनके दिल में है, वही आग मेरे दिल में भी है। जैसे ही फ़ैसला आ जाएगा। विष्णुदेव सरकार को एक घंटा भी नहीं लगेगा कार्रवाई करने में देरी नहीं करेगी।

राजेश मूणत ने कहा कि रविकान्त नाम के एक व्यक्ति का थाने में दर्ज बयान सामने आया है कि उसे उसके दोस्त ने बैंक में खाता खुला दिया। उसके खाते में पैसा आने लगा उसे ही नहीं पता। ऐसे एक नहीं हजारों प्रकरण है। यदि इस तरह के करोड़ों के लेन-देन का मामला संज्ञान में आ गया है, तो फिर कार्रवाई करने में देरी क्यों हो रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के लिए पूर्व में प्रावधान नहीं था। नये नियम में प्रावधान जोड़े गये हैं। इस प्रकरण में जांच जारी है। पूरी ताक़त के साथ इस मामले की जांच की जाएगी। किसी दल की परवाह किए बग़ैर जो जो इस मामले में दोषी पाया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ एक घंटे में कार्रवाई होगी। राजेश मूणत ने कहा कि इस मामले में वही अधिकारी जवाब तैयार कर रहे हैं, जो इस पूरे काकस में शामिल हैं। चंद्रभूषण वर्मा का बयान केंद्रीय एजेंसी ने लिया था। उस बयान का क्या हुआ? किन अधिकारियों को बचाने का काम हो रहा है। महादेव एप मामले में किसी अधिकारी को एक करोड़ महीना, किसी को पचास लाख रुपए महीना दिया गया। ऐसे अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग से यह बताया गया है कि ईडी की तरफ से अब तक सरकार को ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की गई। कोई मछली ही नहीं, मगरमच्छ भी होगा तो ज़रूर पकड़ा जाएगा।

राजेश मूणत ने सवाल उठाया कि जिन लोगों के खिलाफ जांच होनी है, वही सिस्टम में बैठे हैं। वहीं बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने कहा कि पुलिस अधिकारियों और नेताओं के पास भी महादेव एप की आईडी थी। पुलिस अधिकारी जो बार-बार महादेव एप को संरक्षण देते रहे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि क़ानून का राज होना चाहिए। अधिकारियों के संदर्भ में जो चिंता सदस्यों को हैं। बस प्रमाणित होने की देरी है। जैसे ही तथ्य प्रमाणित होगा किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि गृहमंत्री स्टेट प्लेन लेकर यूपी चले जायें और योगी जी से मिल आये। दो-चार लोगों के घरों में बुलडोज़र चलवा दे। बीजेपी विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि यदि युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। तो ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाये। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि अब तक छोटे-छोटे लोगों पर कार्रवाई हुई है। उप मुख्यमंत्री का जवाब पर्याप्त नहीं है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि इस मामले में ईडी जांच कर रही है। जांच अंतिम चरणों में है। राजेश मूणत ने अफसरों पर टिप्पणी की कि आप किसे बचा रहे हैं। ये किसी के नहीं है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ईडी की प्रेस रिलीज में बहुत सारे नाम है। ईडी जैसे ही हमें इसकी अधिकृत जानकारी देगी, हम कार्रवाई करेंगे।

बस्तर में अब लाल सलाम नहीं, जय श्री राम सुना जाएगा : विजय शर्मा

रायपुर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भाजपा सरकार आने के बाद से बीते आठ सप्ताहों में बस्तर के हालात में आए बदलाव का विधानसभा में बखान किया। उन्होंने कहा कि अब पूरा प्रशासन वहां है। आने वाले दिनों में बस्तर में 'लाल सलाम' नहीं, 'जय श्री राम' सुना जाएगा।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सदन में कहा कि बस्तर में आठ हफ़्तों में 47 मोबाइल टावर लगाए गए। आठ हफ़्तों में 35 किलोमीटर रोड बनी। आठ हफ़्तों में 10 नये कैंप खोले गए। आठ हफ़्तों में हैलीकॉप्टर की नाइट लैंडिंग फेसिलिटी शुरू हुई। बस्तर में हम विकास के कैंप खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी सिलगेर गया था। वहां के एक पारा में पिछले एक साल से बिजली नहीं है। सिलगेर के बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं। कलेक्टर बनना चाहते हैं।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि देश को चुनौती देने वाले मुद्दे को दस फ़ीट नीचे ज़मीन में धँस जाना चाहिए और यहां हम भाजपा-कांग्रेस कर रहे हैं। ये वही टेकुलगुडम है, जहां घुसना आसान नहीं था। अब वहाँ कैंप खुल गया है। टेकुलगुड़म में कैंप खुला तो वहां जाना आसान हुआ है। हम अब पूर्ववर्ती की तरफ़ जाएंगे। हम अंदरूनी इलाक़ों में कैंप खोल रहे हैं। कैंप खुलेंगे तो कॉन्फ़्लिक्ट होगा। हमारा प्रयास नक्सलवाद को ख़त्म करने का है।

इससे पहले विपक्ष के सदस्यों ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से प्रदेश में बढ़ रही नक्सली घटनाओं का मामला उठाया। विपक्ष के विधायक द्वारकाधीश अनिला भेड़िया ने गृह मंत्री से पूछा कि पिछले दो महीना में नक्सली घटनाएं क्यों बढ़ रही है? इस दौरान कितनी घटनाएं हुई है कितने जवान शहीद हुए हैं कितने घायल हुए हैं।

गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि दो माह में 19 घटनाएं घटी है, जिसमें चार जवान शहीद हुए हैं और चार सिविलियन मारे गए हैं। उन्होंने यह कहा कि नक्सली घटनाएं क्यों बढ़ रही है इसे समझना होगा। कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने कहा कि आपका इंटेलिजेंस फेल है, इसकी घटनाएं बढ़ रही है।

संक्षिप्त समाचार

निलंबित आईएएस रानू साहू को बड़ा झटका, कोर्ट ने रद्द की जमानत याचिका

बिलासपुर। निलंबित आईएएस रानू साहू को बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब उन्हें जेल में ही रहना होगा। सात जनवरी को मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। मामले में आज आदेश जारी किया गया है। बता दें कि निलंबित आईएएस रानू साहू कोल घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। उन्हें ईडी ने 22 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था। कोल घोटाला मामले को लेकर साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास, घर और दफ्तर में छापा मारा था। इसके बाद ईडी ने इस मामले में रानू के घर छापा मारते हुए लंबे समय से पूछताछ की गई। ईडी द्वारा कथित कोल घोटाले को लेकर रानू साहू पर यह आरोप लगाया कि निलंबित आईएएस रानू साहू के द्वारा कोरबा कलेक्टर रहते हुए कोल लेवी मामले में संलिप्तता पाई गई थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद लोअर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी।

लोकसभा चुनाव 2024 : मतदाता सूची का हुआ अंतिम प्रकाशन

रायपुर। लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने प्रेस कांफ्रेंस की। उन्होंने बताया कि राज्य की तुलना में 24 हजार 109 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। इसमें 1, 01,80,405 पुरुष मतदाता और 1,03,32,115 महिला मतदाता हैं। वहीं 732 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। उन्होंने बताया, छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 2,05,13,252 है। 18 से 19 आयु वर्ग के कुल मतदाता 4,94,452 थे। अंतिम प्रकाशन के बाद कुल युवा मतदाता 5,77,184 हुए हैं। पुनरीक्षण अवधि के दौरान कुल 82,732 मतदाता बढ़े हैं। पुनरीक्षण के दौरान विलोपन में 90,596 मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। 80+ मतदाताओं की संख्या 2,03,326 हैं।

पीएससी महाघोटाले के आरोपियों पर ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर

■ **विष्णु के सुशासन में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं**

रायपुर। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने पूर्व की कांग्रेस सरकार में चर्चित सीजीपीएससी घोटाले के पन्ने खोलने शुरू कर दिए हैं। ईओडब्ल्यू ने मामले में आरोपियों, पूर्व अधिकारियों एवं नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली है। इस केस में सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, तत्कालीन सचिव और आईएएस जीवनकिशोर ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक सहित अन्य ऑफिसर्स और कांग्रेस नेताओं पर ईओडब्ल्यू ने अपराध दर्ज किया है। इनके विरुद्ध धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सीएम विष्णुदेव ने मामले में पूर्व की भूपेश सरकार पर निशाना साधा है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि विष्णु के सुशासन में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कारवाई । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोल परिवहन में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था एवं सुशासन को ध्यान में रखकर खनिज विभाग की ओर से 15 जुलाई 2020 को जारी परिपत्र एवं इसके अनुक्रम में जारी अन्य सभी अनुषंगी निर्देशों को निरस्त करने की घोषणा की।

सीएम ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि सीजीपीएससी महाघोटाले के आरोपी पूर्व अधिकारियों एवं नेताओं पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर दी है। इस महाघोटाले में अपने भविष्य की बलि देने वाले मेरे सभी बच्चों को आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ हुए अन्याय का हिसाब होगा। गुनहगार बचेंगे नहीं, हम आपकी प्रतिभा का सौदा करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे।

सीएम ने तीसरे ट्वीट में लिखा कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार में जिला खनिज न्यास मद में पैसों के बंदरबांट के लिए एक नियम बनाया था, जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ और पैसों की अफरातफरी। भ्रष्ट कांग्रेस सरकार में खनिज विभाग के संचालक द्वारा 15 जुलाई 2020 को आदेश जारी कर यह व्यवस्था दी गई थी कि जिले के खनिज अमले द्वारा ई-परमिट का भौतिक सत्यापन होने के बाद ही ई-ट्रांजिट पास जारी किया जा सकेगा। इस आदेश के माध्यम से इसके पहले जो ऑनलाईन प्रक्रिया थी उसको बंद करके ऑफलाइन किया गया था। जिससे प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप शुरू हुआ, भ्रष्टाचार के आक्षेप लगे और परिवहन में भी विलंब होता था। लेकिन आज छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचारी दीमक रूपी इस नियम को ही खत्म कर दिया।

शीघ्र हो सकती है गिरफ्तारी

सूत्रों के मुताबिक, इस महाघोटाले में जिनके नाम सामने आए हैं, उन्हें नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद बयान दर्ज किया जाएगा। ईओडब्ल्यू जल्द ही इनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है।

क्या है पूरा मामला

राज्य लोक सेवा आयोग ने सीजीपीएससी परीक्षा 2021 के तहत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए 11 मई 2023 को चयन सूची जारी की थी। इसमें टॉप-15 नामों में भाई-भतीजावाद का आरोप लगा है। भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को ज्ञापन सौंपकर सीजीपीएससी मामले की जांच कराने की मांग की थी। विधानसभा चुनाव 2023 में भी यह मुद्दा सुर्खियों में रहा। चुनाव के दौरान बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा, जगह-जगह विरोध प्रदर्शन किए गए थे। भाजयुमो ने नवा रायपुर में पीएससी कार्यालय का घेराव कर करके इसकी जांच कराने की मांग की थी। चुनाव के दौरान पीएम नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने पीएससी घोटाले की जांच कराने की घोषणा की थी। इसके बाद बीजेपी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य सेवा परीक्षा 2021 की गड़बड़ी की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने का आदेश दिया था।

पीएससी के खिलाफ 48 शिकायतें

भूपेश सरकार में सीजीपीएससी के खिलाफ लगभग दो वर्षों में 48 शिकायतें मिली थी। ये सभी शिकायतें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य गृहमंत्री और मुख्य सचिव कार्यालयों में की गई है। कई शिकायतें राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से की गई है। इन शिकायतों में अधिकारियों और नेताओं के रिश्तेदारों को नौकरी देने से लेकर परीक्षा में अनियमितता और भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा, परिणाम में गड़बडी, पक्षपातपूर्ण कार्य के आरोप लगे हैं।

वित्त मंत्री चौधरी की पहल पर रायगढ़ नगर निगम के विकास कार्य के लिए राशि स्वीकृत

■ **स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पेयजल आपूर्ति से जुड़े कामों के लिए मिली मंजूरी**

■ **सड़क और नाली निर्माण के लिए भी राशि स्वीकृत**

रायगढ़। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी की पहल से रायगढ़ नगर को स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पेयजल आपूर्ति से जुड़े 10.61 करोड़ रूपए के कार्यों की स्वीकृति मिली है। इससे शहर में जलापूर्ति के लिए एमएलडी के जीर्णोद्धार, कचरा प्रबंधन व प्लास्टिक रिसाइकलिंग के साथ कचरा संग्रहण व परिवहन के लिए वाहन व मशीनरी की व्यवस्था जैसे काम शामिल है।

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने विशेष पहल करते हुए 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत टाइड एवं अनटाइड मद से रायगढ़ नगर निगम के 10.61 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। जिस पर शासन स्तर से उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साय के निर्देश पर नगर निगम रायगढ़ को विभिन्न विकास कार्यो हेतु 15 वे वित्त आयोग से स्वीकृति प्राप्त हुई।

स्वीकृत कार्यों में मुख्य रूप से शहर के जल समस्या को देखते हुए जल प्रदाय मद अंतर्गत 17 एमएलडी वाटर फिल्टर प्लांट के जीर्णोद्धार हेतु टाईड मद से 1.89 करोड़ रुपए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत कचरा प्रबंधन हेतु ट्रोमेल, बेलिंग, प्लास्टिक रिसाइक्लिंग व्यवस्था हेतु 2.59 करोड़ रूपए के कार्य तथा कचरा संग्रहण और परिवहन हेतु राशि 3.80 करोड़ की राशि से वाहन व मशीनरी क्रय की स्वीकृति शामिल है। इसके साथ ही 15 वे वित्त आयोग की अनटाइड मद से शहर की विभिन्न स्थलों में रोड एवं नाली निर्माण के 21 कार्य जिसकी लागत राशि 2.33 करोड़ रुपए है, उक्त कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा बस्तरवासियों के सपनों को लगेंगे पंख

जगदलपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्विटर पर बस्तरवासियों को खुशखबरी देते हुए ट्वीट कर लिखा है कि बस्तरवासियों के सपनों को पंख लगेंगे, हमारी सरकार ने जगदलपुर से रोजाना विमानों के संचालन के लिए एनओसी दे दी है। इसके लिए आधिकारिक रूप से कलेक्टर द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जगदलपुर एयरपोर्ट का विस्तार भी इसमें सम्मिलित है।

अब बस्तर की जनता के सामाजिक, आर्थिक एवं व्यापारिक कनेक्टिविटी देश एवं प्रदेश के स्थानों में सुगमता से होगी। सभी बस्तरवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। विदित हो कि बस्तर वासियों को अलाइंस विमान सेवा के साथ-साथ अब 31 मार्च 2024 से इंडिगो विमान सेवा प्रारंभ होने से वायु परिवहन सेवा में सुविधाएं बढ़ जाएगी। इंडिगो की विमान प्रतिदिन हैदराबाद से जगदलपुर और रायपुर जाएगी तथा उसी दिन रायपुर से जगदलपुर होते हुए हैदराबाद वापस हो जाएगी।

कार्यालय अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)
Email- gmcmahasmond@gmail.com Phone No. 07723-299171

क्रमांक /761/ क्रय/ शा.चि.म./2024 महासमुंद, दिनांक 06/02/2024

// साफ-सफाई सामग्री, बिजली, एवं प्लम्बिंग सामग्री क्रय हेतु द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना //

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय महासमुंद के द्वारा निविदा क्रमांक /202/क्रय / शा. चि.म./2024 महासमुंद, दिनांक 13.01.2024 के द्वारा आमंत्रित प्रथम निविदा में पर्याप्त मात्रा में फर्मो के लिफाफे प्राप्त नही होने के कारण क्रय समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार द्वितीय निविदा आमंत्रित की जाती है।

महाविद्यालय की वेबसाईट www.gmcmahasamund.edu.in से आनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर प्राप्त करे एवं निर्धारित निविदा प्रपत्र की शुल्क राशि रूपये 500/- (रु. पाँच सौ रूपये मात्र) का अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय महासमुंद (छ.ग.) के नाम से तैयार कर दस्तावेजों के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

- निविदा प्रारंभ तिथि :- 06/02/2024 समय प्रातः 12:00 बजे से।
- निविदा अंतिम तिथि :-19/02/2024. समय दोपहर 01:00 बजे तक।
- निविदा खोलने की तिथि :- 19/02/2024 समय अपराह्न 03:00 बजे ।
- निविदा खोलने का स्थान :-कार्यालय प्रभारी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय महासमुंद

निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट www.gmcmahasamund.edu.in का अवलोकन कर सकते है। निविदा शुल्क की राशि 500/-वापसी योग्य नही है।

अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, महासमुंद (छ.ग.)

जी-07616/5

एयर फोर्स महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी चैंपियन

■ **खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने विजेता टीम को किया पुरस्कृत**

रायपुर। खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने राजनांदगांव जिले में आयोजित महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2024 के विजेता टीम को पुरस्कृत किया। 80वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2024 का फायनल मैच एकतरफा रहा, जिसमें इंडियन एयर फोर्स नई दिल्ली ने पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड नई दिल्ली को 5-1 गोल से हराकर प्रतियोगिता के खिताब पर कब्जा कर लिया। तीसरे व चौथे स्थान के लिए खेला गया मैच भी एकतरफा रहा। जिसमें आर्मी स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड नई दिल्ली ने सेल हॉकी अकादमी राउरकेला को 7-2 गोल से हराकर तीसरे स्थान पर रही।

दिग्विजय स्टेडियम समिति द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेली गई, 80वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के फायनल मैच में एयर फोर्स नई दिल्ली ने पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड नई दिल्ली को 1 गोल के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त देकर प्रतियोगिता के खिताब पर कब्जा किया। इसके पूर्व तीसरे व चौथे स्थान के लिए खेले गए मैच में आर्मी इलेवन ने सेल राउरकेला को आसानी से 7-2 गोल से हराकर तीसरा स्थान किया और सेल की टीम चौथे स्थान पर रही।

प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण करते हुए खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा एवं अन्य अतिथियों ने विजेता टीम को आयोजन समिति द्वारा विशाल चांदी की ट्रॉफी एवं छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री बल्देव सिंह भाटिया द्वारा प्रदत्त 5 लाख रूपए, आयोजन समिति द्वारा उपविजेता टीम को विशाल चांदी की ट्रॉफी एवं समाजसेवी बहादुर अली द्वारा प्रदत्त 3 लाख रूपए, तृतीय स्थान प्राप्त टीम आर्मी इलेवन सी.एन. तिवारी ट्रॉफी एवं श्री रमेश नरेश डाकलिया द्वारा प्रदत्त 51 हजार रूपए और चौथा पुरस्कार सेल अकादमी को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी श्री मृणाल चौबे द्वारा प्रदत्त ट्रॉफी एवं 21 हजार रूपए प्रदान किया गए। प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार एयर फोर्स के पी.ई पोन्नना को पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग द्वारा प्रदत्त आकर्षक ट्रॉफी एवं 5 हजार रूपए, श्री राजेश जैन द्वारा प्रदत्त 'मेन ऑफ द मैच' एवं 'मेन ऑफ द टूर्नामेंट' का पुरस्कार दिया गया। स्पर्धा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी श्री तरूण यादव सेल अकादमी को श्री मनीष कमलेश गौतम द्वारा आकर्षक ट्रॉफी एवं 11 हजार रूपए, स्पर्धा की विजेता उपविपजेता व तीसरे स्थान रही टीम को भिलाई के वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी श्री अनूप श्रीवास्तव द्वारा विशाल आकर्षक कप प्रदान किया गया।

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग
कार्यालय मुख्य अभियंता
महानदी गोदावरी कछार, रायपुर (छ.ग.)

ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना
eProcurement portel : https://eproc.cgstate.gov.in
(प्रथम आमंत्रण)

सिस्टम निविदा क्र. 152408 / निविदा सूचना क्र. 36/ वलेलि/2023-24, बालोद दिनांक 06.02.2024

निम्नलिखित कार्यों के लिए दिनांक 27.02.2024 17:30 तक ऑन लाईन निविदाए आमंत्रित की जाती है:-

कार्य का नाम- बालोद जिले के विकासखण्ड डौण्डीलोहारा की कुरूभाट जलाशय के शीष कार्य का जीर्णोद्वार, मुख्य नहर आर.डी. 0 मी. से 4140 मी. एवं माईनर आर.डी. 0 मी. से 1140 मी. तक का रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य, 06 नग सुपर पैसेज, 04 नग व्ही.आर.बी., 04 नग 01 मी. फाल का निर्माण एवं 19 नग कुलाबा लगाने का कार्य।

अनुमानित लागत- रू. 257.89 लाख

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 13.02.2024 समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड़ किये जा सकते है।

नोट : निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित /पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग, बालोद
कृते मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार
जल संसाधन विभाग, रायपुर, छ.ग.

जी-07590/9

राम रथ से भारत रत्न तक आडवाणी की राजनीतिक यात्रा

सिद्धार्थ शंकर गौतम

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख के बाद लालकृष्ण आडवाणी आरएसएस से जुड़े तीसरे ऐसे नेता हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आशय की घोषणा सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों द्वारा की। भारत के विकास में हमारे दौर के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक रहे आडवाणी जी का योगदान अविस्मरणीय है। उनका सफर जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का रहा है। उन्हें भारत रत्न देने का फैसला मेरे लिए बेहद भावुक घड़ी है। मुझे उनके साथ काम करने और उनसे सीखने के कई बार मौके मिले। प्रधानमंत्री मोदी का आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा करते हुए उक्त संदेश गहरे निहितार्थ लिए हुए है। 2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए प्रथम की सरकार बनने के बाद से आडवाणी राजनीतिक रूप से भाजपा में ही हाशिए पर जाने लगे थे। पाकिस्तान जाकर मोहम्मद अली जिन्ना को सेकुलर बताकर मानो उन्होंने अपनी हिंदुवादी छवि के साथ ही समझौता कर लिया था किंतु उनका यह रूप न तो भाजपा को रास आया और न ही संघ परिवार को। 2013 में गोवा में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जब आडवाणी के स्थान पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया तो आडवाणी सदा के लिए पीएम इन वेटिंग बनकर रह गए। यहां तक कि उन्हें सक्रिय राजनीति से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। यह भाजपा को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले नेता की राजनीतिक यात्रा का पूर्ण विराम था। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी युग में विपक्ष ने कई बार आरोप लगाए कि नरेंद्र मोदी ने आडवाणी के राजनीतिक जीवन की बलि ले ली। जनता का एक बड़ा वर्ग भी यही सोच रखने लगा था किंतु आडवाणी ने अपनी राजनीतिक यात्रा के विराम को लेकर कभी सार्वजनिक रूप से नरेंद्र मोदी को लेकर प्रतिकूल बयानबाजी नहीं की। 2015 में उन्हें पद्म विभूषण भी मोदी सरकार ने दिया। हर वर्ष आडवाणी के जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी उनके निवास पर जाकर उनसे आशीर्वाद लेते रहे। अब आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने की है। आडवाणी को भारत रत्न सम्मान नरेंद्र मोदी की अपने राजनीतिक गुरु को गुरुदक्षिणा है। आडवाणी और मोदी दोनों ने इस घोषणा को भावुक पल बताया है। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा 500 वर्षों से भी अधिक पुराना था। पहले मुगल और बाद के अंग्रेजों के शासनकाल में भी यह मुद्दा सर्वहिंदू समाज का मुद्दा नहीं बन सका था। स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने भी राम मंदिर मुद्दे में एक प्रकार से हाथ न जलाने का अघोषित निर्णय ले रखा था। लेकिन 1990 में आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा ने राम मंदिर मुद्दे को हिंदू समाज के अधिकांश घरों तक पहुंचा दिया था। इससे राजनीतिक रूप से भाजपा और आडवाणी को क्या लाभ हुआ, इसका आंकलन भिन्न हो सकता है किंतु राम भारत की आस्था हैं, इस भाव का देशव्यापी जागरण आडवाणी की रथयात्रा को जाता है। समस्त धर्मगुरुओं ने जो कार्य दशकों में नहीं किया था वह आडवाणी की राम रथयात्रा ने कर दिया था। आडवाणी की उपस्थिति ने राम मंदिर मुद्दे को सामाजिक वैधता प्रदान की जिसकी मजबूत नींव पर पत्थर रखकर आज हिंदूवादी राजनीति अपने चरम पर है। ये वही आडवाणी थे जिन्होंने जननेता की छवि न होने के बाद भी भाजपा को हिंदुओं की पार्टी का तमगा दिलवाया। 23 अक्तूबर, 1990 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री वीपी सिंह के कहने पर समस्तीपुर में आडवाणी की रथयात्रा को रोककर उन्हें गिरफ्तार करवाया तो संभवत: राजनीति के दोनों चतुर खिलाड़ियों को अंदेशा नहीं होगा कि उनका यह कदम उनकी राजनीतिक जमीन को बंजर कर देगा। और हुआ भी यही। वीपी सिंह प्रधानमंत्री न रह पाए और लालू प्रसाद यादव की छवि मुस्लिम परस्त बनकर रह गई जिसका परिणाम आज तक लालू परिवार भुगत रहा है। आज यदि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो इसमें आडवाणी द्वारा फैलाई गई जनचेतना की महत्वपूर्ण भूमिका है।

प. उत्तरप्रदेश में अजेय होना चाहती है भाजपा

समीर चौगांवकर

मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने से मना करने के बाद अब मोदी और शाह की योजना जयंत चौधरी को अपनी ओर करने की है। ऐसा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी 14 सीटों को जीतने के लिए करना चाहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्व रखता है इसको इस बात से समझा जा सकता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के ठीक तीन बाद 25 जनवरी को मोदी ने कल्याण सिंह की कर्मभूमि रही बुलंदशहर में रैली की। मोदी ने इस रैली में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद किया और कई बार राम मंदिर आंदोलन में उनके योगदान और राम मंदिर का जिक्र किया। मोदी ने अपने भाषण को विकास से ज्यादा राम पर केन्द्रित किया। मोदी उत्तर प्रदेश की इस भूमि से हिन्दुत्व का संदेश देकर गए।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की थी। वो 2014 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगो का जिक्र कर हिन्दुओं को जागृत होने का संदेश दे गए थे। 2014 में मोदी के संदेश का असर ऐसा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी 14 सीटें जीत गई थी। लेकिन 2019?के आम चुनाव में इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने भाजपा को तगड़ा झटका दिया था जब इस क्षेत्र से भाजपा 7 सीटें हार गयी थी। से सीटें थीं, बिजनौर, सरहानपुर, अमरोहा, नगीना, संभल, मुरादाबाद और रामपुर। 2019 में बसपा, सपा और जयंत चौधरी की आरएलडी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। बहुजन समाज पार्टी ने बिजनौर, सहारनपुर, अमरोहा और नगीना सीट जीती थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने संभल, मुरादाबाद और रामपुर सीट जीती थी।

भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर और कैराना लोकसभा सीट जीती थी। इसीलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इस क्षेत्र में हिन्दुत्व को आगे रखकर अपनी चुनावी रणनीति का तानाबाना बुन रही है। 25 जनवरी को बुलंदशहर में मोदी की रैली के दौरान जनता के जय श्री राम का नारा लगाने पर मोदी का मंद मंद मुस्कराना और नारों के बीच कुछ सेंकड के लिए अपना भाषण रोक देना इस बात को बताने के लिए काफी था कि इस बार राम मंदिर का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है जो मोदी के लिए संतोष की बात है।

किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे इस क्षेत्र में संगठन को चुस्त दुरूस्त करने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले साल जून में कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक कर संगठन को सक्रिय कर दिया था। वहीं 2019 में हारी 7 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व संगठन महामंत्री सुनील बंसल को इन हारी हुई 7 सीटों का प्रभारी बनाया गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, समुदाय को लेकर कह दी बड़ी बात. भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, समुदाय को लेकर कह दी बड़ी बात. इन हारी हुई सीटों पर मोदी सरकार के एक केन्द्रीय मंत्री को क्षेत्र में लगातार भेजकर संवाद से समर्थन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अलावा इन सीटों पर राज्यसभा सांसदों को %विकसित भारत संकल्प यात्रा% की जिम्मेदारी सौंपकर मोदी की योजनाओं को घर घर तक पहुचाने के काम पर लगाया गया है।

पश्चिमी उत्तर पद्रेश के जाट मतदाताओं को भाजपा कितनी गंभीरता से ले रही है, इसको इस बात से भी समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार भाजपा ने किसी जाट भूपेन्द्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपकर जाटों को संदेश देने की कोशिश की है। फिर भी पश्चिमी यूपी में जातिगत समीकरण साधना भाजपा के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। पश्चिमी यूपी में दरकते जाट वोट को साधने के लिए मोदी और शाह हर संभव कोशिश कर रहे है। जयंत चौधरी के अखिलेश के साथ गठबंधन होने के बाद भी अमित शाह इस कोशिश में जुटे हैं कि जयंत को सम्मानजनक स्थान देकर एनडीए में लाया जाए। खबर है कि अमित शाह खुद जयंत से दो बार बात कर चुके हैं। मोदी ओर शाह की जोड़ी जानती है कि उत्तर प्रदेश में मायावती के अखिलेश से अलग होने के बाद अब यदि जयंत चौधरी को भी अखिलेश से अलग कर दिया जाता है तो पश्चिमी यूपी की सभी 14 सीटें जीतने में भाजपा की राह आसान हो जाएगी।

2019 के चुनाव में जयंत चौधरी की आरएलडी सपा के साथ गठबंधन में मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा सीट पर लड़ी थी और तीनों सीटों पर हार गई थी। हालांकि बाद में जयंत चौधरी अखिलेश यादव के सहयोग से राज्यसभा भेजे गए थे। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को सात सीटें देने की घोषणा की है लेकिन जयंत चौधरी राम मंदिर का असर भी जमीनी स्तर पर महसूस कर रहे हैं। जयंत चौधरी जानते हैं कि मायावती के अलग होने के बाद सिर्फ सपा उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकती है। जयंत चौधरी पर 2022 में उनके जीते हुए आठ विधायक भी इस बात का दबाव बना रहे हैं कि जयंत भाजपा से गठबंधन की राह तलाशें जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार और केन्द्र की सरकार में कुछ हिस्सा आरएलडी को मिल सके।

अगर जयंत चौधरी एनडीए में चले जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 77 सीटें जीतने के अपने लक्ष्य के करीब पहुच जाएगी। जबकि समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम गठजोड़ के भरोसे है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान खासतौर पर पश्चिमी यूपी के मुसलमानों को अखिलेश के साथ एकजुट करने में जुटे हैं। ऐसे में जयंत चौधरी सपा का साथ छोड़ते हैं तो अखिलेश यादव के जाट मुस्लिम गठजोड़ की कोशिश का धराशाही होना तय है। लोकसभा से इतर अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो 2022 में पश्चिमी यूपी की 71 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 41 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 22 और राष्ट्रीय लोकदल ने 8 सीटें जीती थी। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। 2022 के विधानसभा चुनाव में 17 जाट विधायक उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे थे, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में 14 जाट विधायक विधानसभा पहुंचे थे। उस समय 13 जाट विधायक भारतीय जनता पार्टी से थे और एक आरएलडी से था।

इसलिए इतना तो कहा ही जा सकता है कि जमीनी स्तर पर पश्चिमी यूपी में भाजपा दूसरे दलों से अधिक मजबूत स्थिति में है। लेकिन अब जयंत चौधरी को साथ लाकर वह अजेय होना चाहती है। जयंत चौधरी भाजपा के साथ आते हैं या सपा के साथ रहते हैं, यह आने वाले कुछ दिनों में तय होगा लेकिन यह तय है कि उत्तर प्रदेश की असली लड़ाई पश्चिमी यूपी में देखने को मिलेगी जहां भाजपा मोदी के काम से ज्यादा राम के नाम और जातिगत समीकरणों पर दांव चलेगी। यहां भाजपा मोदी मैजिक पर निर्भर है और मोदी राम के नाम पर निर्भर हैं। ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है इसमें काई दो राय नहीं।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-2)

गतांक से आगे...

पाँचवें अध्याय में अज्ञान एवं ज्ञान की भूमिका, %स्वरूप% में स्थिति मोक्ष और स्वरूप से नष्ट होना बन्धन, ज्ञान एवं अज्ञान की सात भूमिकाएँ, जीवन्मुक्त का आचरण, ज्ञान भूमिका का अधिकारी, ब्रह्म की अनुभूति ही ब्रह्म प्राप्ति का उपाय, मनोलय होने पर चैतन्य की अनुभूति, जगत् के भ्रामक ज्ञान को शान्त करने का उपाय, विषयों से उपरामता, तृष्णा को नष्ट करने का उपाय अहंभाव का त्याग, मन के अभ्युदय एवं नाश से बन्धन-मुक्ति, चित् (चैतन्य) विद्या का अधिकारी, माया से बचकर ही ब्रह्म प्राप्ति सम्भव, ब्रह्म की सृष्टि माया के अधीन तथा संकल्प (आकांक्षा) के नष्ट होने से संसार का मूलोच्छेदन सम्भव जैसे विषयों का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है।

छठे अध्याय में समाधि के अभ्यास से परमेश्वरत्व की प्राप्ति, ज्ञानियों की उपासना पद्धति, अज्ञानियों की दु:खद स्थिति, मनोनाश का उपाय, वासना त्याग का उपाय, जीवन्मुक्त की महिमा, तृष्णा की त्याग विधि, चार प्रकार के निश्चय, अद्वैतनिष्ठ व्यक्ति के लिए संसार का अभाव, मुमुक्षु की ब्रह्मनिष्ठता और अन्त में इस उपनिषद् शास्त्र के पठन-पाठन का प्रतिफल वर्णित है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यह महोपनिषद् अपने नाम के अनुसार अनेकानेक महत्त्वपूर्ण विषयों का बड़ी कुशलता के साथ विशद विवेचन प्रस्तुत करके अध्यात्मपथ के पथिकों का समुचित मार्गदर्शन करती है।

हे परमेश्वर! मेरे समस्त अंग-अवयव वृद्धि को प्राप्त करें। वाणी, चक्षु, कर्णेन्द्रिय आदि समस्त कर्मेन्द्रियाँ एवं ज्ञानेन्द्रियाँ, समस्त प्राण, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति ओजस्-तेजस् से परिपुष्ट एवं विकसित हों।

क्रमश: ...

युद्ध और कूटनीति पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र

अभिनय आकाश

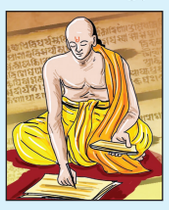

चाणक्य की साम, दाम, दंड, भेद वाली नीति से तो आप सभी वाकिफ हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के सिद्धांत भी बड़े काम के हैं। इसमें निम्नलिखित रणनीतियाँ शामिल हैं- संधि (ट्रीटी), विग्रह (संधि तोड़ना और युद्ध शुरू करना), आसन (तटस्थता), यना (युद्ध के लिए मार्च की तैयारी), सामश्रय (समान लक्ष्य रखने वालों के साथ हाथ मिलाना) और अंत में द्वैदभाव (दोहरी नीति यानी एक दुश्मन से कुछ समय के लिए दोस्ती और दूसरे से दुश्मनी)। तमाम तरह की स्थितियाँ हमारे समाज में हर जगह उभरती रहती हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में हमारी रक्षा सभी क्षेत्रों में। हम इसे कैसे प्रबंधित करें? चाणक्य को दुनिया में आदर्शवादी नहीं बल्कि सबसे पुराने, सर्वश्रेष्ठ यथार्थवादी के रूप में जाना जाता है। चाणक्य के पास भावना के लिए कोई जगह नहीं थी। जिस चाणक्य को हम इतना अच्छे से जानते हैं। हर घर के अंदर रोजाना कोई न कोई चाणक्य नीति की बात होती है। उस चाणक्य को देश में कितनी जगह मिली है।

अर्थशास्त्र के तीन उद्देश्य:-

रक्षा- जब तक राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, वो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। चाणक्य का कहना था सुरक्षा पहले बाकी सब बाद में। सुरक्षा देश के बॉर्डर और यहां के नागरिकों की। आपका पड़ोसी आपका मित्र नहीं हो सकता। राजा या शासक को राज्य में केंद्रीय व्यक्ति माना जाता है। ये महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने, कानून और व्यवस्था बनाए रखने, राज्य की रक्षा करने तथा लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार होते हैं।

पलाना- शासक को अपने क्षेत्र (पालना) की रक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

योगक्षेम- लोगों के कल्याण की रक्षा करना। कौटिल्य के लिए, विदेश नीति का पैमाना यह है कि क्या यह राज्य को गिरावट, यथास्थिति और उन्नति के चक्र में आगे बढ़ने की अनुमति देती है। विदेश-नीति के लक्ष्य क्षेत्र की सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक कल्याण प्रदान करने से भी संबंधित हैं, और दोनों एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। इसलिए, भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति में पाकिस्तान और चीन जो संभावित भूमिका निभा सकते हैं, वह काफी हद तक उनके प्रति भारत के दृष्टिकोण को परिभाषित करना चाहिए। इससे यह स्पष्ट रूप से बताने में मदद मिलेगी कि भारत का राष्ट्रीय हित क्या है और यह एक वैश्वीकृत, अन्योन्याश्रित दुनिया में अपनी विदेश नीति के लक्ष्य- योगक्षेम (सुरक्षा और कल्याण) को कैसे परिभाषित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांगरी ला डायलॉग में अपने मुख्य भाषण में भारत की भविष्य की आर्थिक संभावनाओं को न केवल देश की अर्थव्यवस्था के पैमाने से जोड़ा, बल्कि इसके वैश्विक जुड़ाव की गहराई से भी जोड़ा। क्षेत्र में राज्यों की परस्पर निर्भर किस्मत प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग को विशेषाधिकार देने का एक सम्मोहक मामला बनाती है। नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए भारत का प्रयास कल्पनाशील रूप से सुरक्षा और समृद्धि के दोहरे लक्ष्यों को लक्षित करता है।

महाशक्तियों से रिश्ते बिगाड़ चुका है ट्रूडो का मिजाज

दीपक वोहरा

रामायण में भगवान राम के भरोसेमंद सखा हनुमान जी को अपनी महान शक्ति को भूलने का श्राप मिला है। भालुओं के राजा जामवंत उन्हें याद दिलाते हैं और बाकी की कहानी सब जानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि शताब्दी के तीसरे दशक में भारत अच्छाई की शक्ति के रूप में उभर रहा है और इसकी प्रतिष्ठा आसमान छू रही है। न केवल इसकी अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है, बल्कि इसकी वैज्ञानिक क्षमता और नए डिजिटल भविष्य की दिशा में इसका नेतृत्व भी स्पष्ट है।

विकासशील दुनिया भारत के नेतृत्व को स्वीकार करती है और उसका अनुकरण भी करना चाहती है। शक्तिहीन होती पाश्चात्य शक्तियां इससे भयभीत हैं। भारत की नीति हमेशा स्वतंत्र एवं स्वायत्त रही है। जाहिर है, खुद को ब्रह्मांड का मालिक मानने वाले देश हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चूंकि अब कोई जामवंत नहीं है, नशे के आदी विदूषकों के राजा (ट्रूडो) ने, जो वैश्विक मंच पर जगह बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, अपनी खुफिया सेवाओं को भारत के खिलाफ हास्यास्पद आरोप लगाने का फरमान जारी किया।

सबसे पहले उसने यह बेतुका आरोप लगाया कि भारत ने उसके वफादार व्यक्ति की हत्या कर दी है। उसने दुनिया भर को इसके बारे में बताया। लेकिन जब उसका ज्यादा असर नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी खुफिया सेवाओं को भारत पर कनाडा के चुनाव में हस्तक्षेप करने और उसकी लोकतांत्रिक संस्थानों को नष्ट करने की योजना बनाने के आरोप लगाने का आदेश दिया। कोई पूछ सकता है कि इसका सबूत क्या है?

खैर, कनाडा में भारतीय प्रवासियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो भारत-हितैषी उम्मीदवारों को वोट दे सकता है। वे भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक हैं और कनाडा के कानून के तहत ही उन्हें कनाडाई नागरिकता मिली है। लेकिन ट्रूडो विलाप करते हुए

कहते हैं, 'हम कानून के राज में विश्वास करते हैं, लेकिन गैर-श्वेत कनाडाई लोगों ने अब तक कनाडाई झंडे को नहीं अपनाया है।' लेकिन ट्रूडो ने क्या कभी इसकी वजह सोची है? कनाडा भारतीय मूल के प्रवासियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। हालांकि विदूषक ट्रूडो शेखी बघारते हैं कि वे लोकतांत्रिक और सबको समान अवसर देने वाले लोग हैं, पर वास्तविकता में वे नस्लवादी हैं। कनाडा एक छोटी शक्ति वाला बड़ा देश है, और उसे सम्मान व प्रशंसा पाने की प्रबल इच्छा है। इसलिए वह अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपनी नाक घुसेड़ता है, और विवेकशील लोग उसकी आंखों में खटकने लगते हैं। तमिल विद्रोह के दौरान कनाडा ने श्रीलंका पर मानवाधिकारों के उल्लंघनों के बारे में खूब शोर मचाया, जवाब में, श्रीलंका ने भी लिट्टे आतंकवादियों को शरण देने का उन पर आरोप लगाया।

श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवादियों को कनाडा में सुरक्षित पनाहगाह मिल गई है और वह भारत के खिलाफ ट्रूडो की टिप्पणियों से %हैरान नहीं% हैं, क्योंकि अपमानजनक और बेबुनियाद आरोप लगाना उनकी आदत है। विदूषक ट्रूडो पाकिस्तान (खासकर बलूचिस्तान और खैबर क्षेत्र) में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के बारे में चुप हैं, क्योंकि प्रमुख कनाडाई कंपनियां वहां खनन में शामिल हैं। 1980 के दशक में एक कनाडाई खनन कंपनी बंद हो गई, जब यह साबित हुआ कि इंडोनेशिया में सोने के विशाल भंडार की खोज के बारे में उसने बेशर्मी से झूठ बोला था। अपने सहयोगियों के समर्थन के बिना कनाडा की सेना भूटान जितनी ही मजबूत है। उसने यूक्रेन से जिन हथियारों का वादा किया, वह अब तक बन भी नहीं पाए हैं।

आधुनिक इतिहास में पहली बार एक संपन्न, बड़े और कम आबादी वाले पश्चिमी देश के प्रधानमंत्री ने सबसे ताकतवर विकासशील देश से अपने रिश्ते को यह आरोप लगाकर खत्म कर दिया कि उसने, उसके सबसे प्रिय आतंकवादी, जो भारतीय मूल का कनाडाई नागरिक था, की कनाडा की धरती पर हत्या कर दी। उन्होंने इस घटना को वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया। लेकिन भारत ऐसा क्यों करना चाहेगा, उसे इससे क्या हासिल होगा? ट्रूडो इसका जवाब नहीं देंगे कि क्या वह व्यक्ति भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने और टेरर-फंडिंग में शामिल था, और क्या उसने कनाडा में असॉल्ट राइफल लहराते हुए अपने वीडियो पोस्ट किए थे? इसलिए भारत के विदेश मंत्री ने नवंबर, 2023 में लंदन में कहा कि कनाडा चाहता है कि हम उसकी धरती पर एक कनाडाई की हत्या की जांच में %सहयोग% करें, लेकिन वह हमें यह भी बताने में असमर्थ है कि वह किस तरह के सहयोग की अपेक्षा करता है।

कनाडा की अहंकारी विदेश मंत्री, जिसने भारत को धमकी दी थी कि वह आतंकी की हत्या में भारत की संलिप्तता के बारे में अपने सहयोगियों से बात करेंगी, अब भारत की प्रतिक्रिया से हिल गई हैं और भारत से निजी तौर पर इस मसले पर बात करना चाहती हैं। तो अब आगे क्या होगा? मैं पिछले पचास वर्षों से कूटनीति में हूं। राष्ट्रों के बीच भरोसा कायम करने में दशकों लग जाते हैं। लेकिन रिश्ते खराब करने के लिए कुछ गलत बयान ही काफी होते हैं।

भारत एक परिपक्व और शक्तिशाली लोकतंत्र है। विदेश नीति को लेकर विभिन्न दलों में यहां आम सहमति है। ट्रूडो ने कई प्रमुख शक्तियों के साथ अपने रिश्ते खराब किए हैं। उन्होंने पुतिन को बेवजह गालियां दीं, चीनी नेता ने कनाडाई मीडिया को उनकी गोपनीय चर्चाओं के बारे में जानकारी देने के लिए 2022 में बाली में सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और जब उन्होंने जी-7 शिखर सम्मेलन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया, तो अमेरिका भी नाराज हो गया था।

जब एक अमेरिकी-कनाडाई आतंकवादी ने एयर इंडिया के विमानों को उड़ाने की धमकी दी, तो ट्रूडो ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो अगर कुछ अप्रिय हुआ, तो क्या इसे ट्रूडो के कानून के मुताबिक कार्रवाई की स्वतंत्रता माना जाए? भारत-कनाडा संबंधों को सुधारने में दशकों लगेंगे। कनाडा हमारी विदेश नीति के रडार पर बहुत नीचे है। ट्रूडो भारत पर रिश्ते तोड़ने का भी आरोप लगा सकते हैं, तो हम इसमें आखिर क्या कर सकते हैं! ओटावा एक समय वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों के लिए अच्छी पोस्टिंग थी। लेकिन फिलहाल वह भारतीय कूटनीतिज्ञों के लिए अच्छी जगह नहीं रह गई है। उम्मीद है, इस बार मोदी फिर चुनाव जीतकर सत्ता में लौटेंगे। यदि तब तक ट्रूडो का नशा उतर जाए, तो वह उन्हें बधाई दे सकते हैं। हो सकता है, इससे रिश्ते में थोड़ी गर्मजोशी आए।

आज का इतिहास

1971 अपोलो 14 मिशन चांद से पृथ्वी पर लौटा।
1975 रूसी अंतरिक्ष यान सोयुज 17 अंतरिक्ष से 29 दिन बाद धरती पर लौटा।
1976 ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल का गठन ऑस्ट्रेलियाई सेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना के एकीकरण द्वारा किया गया था।
1979 अफ्रीकी देश नाइजीरिया में संविधान बदला गया।
1992 अलजीरिया के संसदीय चुनावों में इस्लामी प्रवृत्ति वाले धड़े की भारी सफलता के बाद सत्तासीन सैनिकों ने चुनावों के परिणामों को निरस्त और अलजीरिया इस्लामी मुक्तिमोर्चे को गैर कानूनी घोषित किया।
1995 न्यूयॉर्क शहर के कोर्ट थिएटर में खोले गए हेइरेस नामक गुप्त प्रदर्शन को 340 प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई।
1997 डेड्यू रेनॉल्ड जो एक प्रसिद्ध कॉमेडियन थे, उन्हें 1997 में आयोजित 11 वें अमेरिकी कॉमेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
1998 जॉर्जियाई राष्ट्रपति एडुअर्ड शेवर्नडज़े पर पारित किया गया असाइनमेंट प्रयास प्रयास के परिणामस्वरूप विफल रहा।
2001 अमेरिकी पनडुब्बी यूएसएस ग्रीनविले गलती से उवाजीमा फिशरी हाई स्कूल द्वारा संचालित एक जापानी प्रशिक्षण पोत एहिम मारू से टकरा गई।
2002 XIX शीतकालीन ओलंपिक वर्ष 2002 में यूटा या क्यूबेक सिटी नामक साल्ट लेक सिटी में खुलता है।
2007 पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी जमायती उलेमा इस्लामी ने जिन्ना को स्वतन्त्रता सेनानी की सूची से हटाया।
2010 फ्रामर फिलीपीन के राष्ट्रपति गुएरिन मैकापगल- अरोयो और 196 अन्य पर नवंबर 2009 में मागुइंडानाओ नरसंहार से संबंधित हत्या के मामले में आरोप लगाए गए हैं।
2011 विकी लीक्स ने कहा कि सऊदी अरब ने अपने कच्चे तेल के भंडार को 40% बढ़ा दिया है जो कि गार्जियन द्वारा प्रकाशित किया गया है।
2013 एनेट स्कोवन जो शिक्षा और अनुसंधान के जर्मनी के संघीय मंत्री थे, ने डसेलडोर्फ विश्वविद्यालय द्वारा साहित्यिक चोरी के लिए डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
2014 देश स्विट्जरलैंड ने यूरोपीय संघ से देश में आने वाले प्रवासियों की संख्या के बारे में कोटा देने के लिए वोट दिया और लगभग 50.4% मतों ने इस उपाय को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की।

महाराष्ट्र में एनडीए की राज्यसभा सीटें जीतने की रणनीति

हरीश गुप्ता

2024 के लोकसभा चुनावों में अपनी सीट और वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित भाजपा आलाकमान राज्यों में अपने सहयोगियों से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कह रहा है। इस रणनीति के तहत पार्टी महाराष्ट्र में अजित पवार के नेतृत्व वाली अपनी प्रमुख सहयोगी राकांपा को बारामती, सतारा, शिरूर और रायगढ़ की सभी चार सीटें छीनने के लिए उकसा रही है; जो 2019 के लोकसभा चुनावों में राकांपा (शरद पवार गुट) के पास थीं। शरद पवार ने यह स्पष्ट संदेश देने के लिए अपनी बेटी सुप्रिया सुले को अपनी पारंपरिक बारामती लोकसभा सीट से खड़ा किया था कि वह उनकी उत्तराधिकारी होंगी। लेकिन स्थिति में तब नाटकीय मोड़ आ गया जब अजित पवार ने पार्टी के अधिकांश विधायकों को अपने साथ लेकर भाजपा से हाथ मिला लिया।

दिल्ली में भाजपा मुख्यालय से आने वाली रिपोर्टों में कहा गया है कि अजित पवार को सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती लोकसभा से अपनी पत्नी को मैदान में उतारने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि पीएम मोदी और पवार के बीच कई दशकों से निजी केमिस्ट्री चली आ रही है। लेकिन समय बदल गया है और अंदरूनी सूत्रों की मानें तो भाजपा इस महीने होने वाले द्विवार्षिक चुनावों में सभी छह राज्यसभा सीटें जीतने की रणनीति बना रही है। एनडीए पांच सीटें जीतने में कामयाब हो सकता है, लेकिन कई रणनीतिकार दावा करते हैं कि अगर विपक्ष के कुछ विधायक भाजपा के हाथों खेल जाएं तो एनडीए छह सीटें जीत सकता है।

288 के सदन में कांग्रेस के 41

विधायक हैं और न ही राकांपा (शरद पवार) और न शिवसेना (उद्धव) अपने दम पर एक सीट जीत सकते हैं। ऐसी खबरें हैं कि वरिष्ठ पवार बारामती में सहानुभूति फैक्टर का आह्वान करते हुए कह सकते हैं कि यह उनके जीवन का आखिरी चुनाव होगा। यह काम करेगा या नहीं, इसका परीक्षण तो मई में ही हो सकेगा।

भारतीय राजनीति के महान 'पलटू राम' ने लगभग 45 साल पहले हरियाणा में देखे गए 'आया राम, गया राम' के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जब मध्यस्थ एक बार फिर गठबंधन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा नेतृत्व के बीच शांति समझौता करा रहे थे, तो एक अड़चन आ गई। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद नीतीश कुमार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से नया नियुक्ति पत्र चाहते थे। वह चाहते थे कि उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया जाए और साथ ही भाजपा उन्हें अपना समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंप दे।

वह यह भी चाहते थे कि राज्यपाल उन्हें उसी समय नया नियुक्ति पत्र सौंप दें। नीतीश ने इस बात पर भी जोर दिया कि शपथ ग्रहण समारोह उसी दिन आयोजित किया जाए। भाजपा के लिए यह विकट स्थिति थी क्योंकि उसके विधायकों ने नीतीश कुमार को अपना समर्थन देने के लिए कोई बैठक नहीं की थी ताकि पार्टी राज्यपाल को नीतीश कुमार को समर्थन देने का पत्र सौंप सके।

नीतीश कुमार बेहद शक्की स्वभाव के हैं और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शर्तें पूरी होने पर ही समझौता किया जा सकता है। भाजपा इस शर्त के साथ सभी शर्तों पर सहमत हुई कि लोकसभा सीट साझाकरण समझौता मेरिट के आधार पर होगा, न कि 2019 के नतीजे के आधार पर। पर्दे के पीछे के इन पेचीदा समझौतों के बाद ही भाजपा नीतीश कुमार के साथ सत्ता साझेदारी समझौते पर वापस लौट सकी। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए का प्रमुख भी नियुक्त किया गया है।

जब से मोदी सरकार ने 2023 में समाजवादी नेता दिवंगत मुलायम सिंह यादव को पद्मविभूषण दिया है, तब से आरएसएस और कट्टर भाजपा कार्यकर्ता परेशान थे। आखिरकार, वह यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार ही थी जिसने 30 अक्तूबर 1990 को कारसेवकों और पुलिस के बीच झड़प के बाद अयोध्या में रामभक्तों पर गोलियां चलवाई थीं।

आयोजक-विहिप, आरएसएस और भाजपा-बाबरी मस्जिद स्थल पर राम मंदिर चाहते थे लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं था कि कारसेवक मस्जिद के साथ क्या करेंगे। इसलिए संघ परिवार यादव को पुरस्कार दिए जाने को लेकर बिना कुछ कहे नाराज चल रहा था। याद करें कि 2003 में आरएसएस विचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी ने जब तक के.बी। हेडगेवार (आरएसएस संस्थापक) और एम.एस। गोलवलकर (आरएसएस विचारक) को भारत रत्न नहीं दिया जाता, तब तक पद्मभूषण पुरस्कार लेने से इंकार कर दिया था। ठेंगड़ी को यह पुरस्कार वाजपेयी सरकार ने देने की घोषणा की थी।

आरएसएस दशकों से इन पुरस्कारों पर चुप्पी साधे हुए है। इसलिए जब मोदी सरकार ने आडवाणी को भारत रत्न दिया तो कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन आम भाजपा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं क्योंकि आडवाणी को एक महान व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने भाजपा को दो लोकसभा सीटों से 182 तक पहुंचाया और राम मंदिर आंदोलन के माध्यम से पार्टी को सत्ता में लाए। हाल ही में मोदी सरकार पार्टी कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत कर रही है और राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीन मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति इस नई सोच का संकेत है।

पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में ऐलान किया कि भाजपा 370 सीटें जीतेगी और एनडीए 400 सीटों का आंकड़ा पार कर जाएगा। लक्ष्य हासिल करने के लिए भाजपा अब महाराष्ट्र, बिहार और अन्य जगहों पर चुनाव लड़ने के लिए अपने सहयोगियों से अधिक सीटें हासिल करने की तैयारी कर रही है।

उदाहरण के लिए, वह चाहती है कि नीतीश कुमार 17 के बजाय 10-12 सीटों पर ही चुनाव लड़ें। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनावों में नीतीश कुमार को अपनी पांच सीटें दे दी थीं। अब वह इन्हें 2024 के चुनावों में वापस चाहती है। इसी तरह महाराष्ट्र में भाजपा 30 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है।

जबकि 2019 में भाजपा ने संयुक्त शिवसेना के साथ गठबंधन कर राज्य में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वह चाहती है कि शिवसेना (शिंदे गुट) और अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा केवल उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़े, जहां वह जीत सकती है। इन पेचीदा मुद्दों पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है।

पूर्वोत्तर में राजनीतिक अस्थिरता विकास की राह में रोड़ा

पीएस वोहरा

पूर्वोत्तर के राज्य आम जन के मुद्दों में ज्यादा सम्मिलित नहीं रहते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, परंतु इन्हें आर्थिक विकास में लगातार दूसरे राज्यों के समान प्रोत्साहन मिलना जरूरी है, जो इनका लोकतांत्रिक अधिकार है तथा यह देश के तेजी से आर्थिक विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। हालांकि पिछले दिनों मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया अंतरिम बजट आने वाले चुनावों की छत्रछाया में बनाया गया बजट नहीं था, कुछ दूरगामी सोच रखे हुए था। फिर भी यह अब अत्यंत अपेक्षित हो गया है कि आने वाली नई सरकार जब अपना पूर्ण वित्तीय बजट पेश करे, तो उसमें इन आठ पूर्वोत्तर राज्यों-अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा पर एक विशेष आर्थिक नीति शामिल हो। ये राज्य भारत की सामरिक संरचना के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनकी वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए आशंका है कि पूर्वी एशिया महाद्वीप के पड़ोसी मुल्क, जिनमें चीन भी शामिल है, इन राज्यों में परोक्ष रूप से अपनी भागीदारी न बढ़ा लें। इससे भारत के लिए बहुत विपरीत स्थिति पैदा हो सकती है। पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुसार, अन्य दूसरे राज्यों की तुलना में भारत के ये आठ पूर्वोत्तर राज्य अपने आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए वित्तीय कर्ज अथवा केंद्र सरकार से मिलने वाले वित्तीय करों में हिस्सेदारी पर अधिक निर्भर रहते हैं। मिजोरम की अर्थव्यवस्था में 87 फीसदी वित्तीय आय केंद्र सरकार के वित्तीय करों में हिस्सेदारी तथा केंद्र सरकार से प्राप्त विशेष अनुदान से हो रही है। गौरतलब है कि 15वें वित्त आयोग के मुताबिक, पिछले वर्ष में पूर्वोत्तर के इन आठ राज्यों की वित्तीय कर्ज में देनदारी 33 फीसदी से ज्यादा है। असम हालांकि बेहतर स्थिति में है, जहां पर वित्तीय कर्ज जीडीपी का मात्र 25 फीसदी है। मुख्य समस्या इस बात की है कि इन राज्यों में अर्थव्यवस्था की विकास दर तथा उसका जीडीपी बहुत अधिक अस्थिर रहता है। इस कारण राज्यों के वित्तीय करों के स्रोत बहुत कम रह जाते हैं, जिसके चलते इन्हें वित्तीय सहायता हेतु केंद्र सरकार पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है। यहां पर यह समझना भी अत्यंत आवश्यक है कि इन राज्यों में आर्थिक विकास का मुख्य आधार कृषि तथा सेवा क्षेत्र ही है। सेवा क्षेत्र में पर्यटन मुख्य आधार है, लेकिन बुनियादी ढांचों का अच्छी तरह विकसित न होना इस संबंध में एक मुख्य समस्या बन जाता है। मोदी सरकार ने पिछले समय से इन राज्यों के लिए चली आ रही नॉर्थ ईस्ट की नीति को बदलकर एक्ट ईस्ट नीति बनाई, जिसके अंतर्गत वाणिज्य, संस्कृति और संपर्क को मुख्यधारा में रखा गया है। लेकिन इन राज्यों में लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता और भौगोलिक चुनौतियों के कारण आधुनिक औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप पर्याप्त संरचना का विकास नहीं हो पाया है। इन राज्यों के विकास में एक अवरोध निजी निवेश का न होना भी है। एक मुख्य समस्या यह भी है कि इन राज्यों की वित्तीय आय तथा केंद्र से मिले अनुदानों का बहुत बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन तथा वित्तीय कर्जों के ब्याज के भुगतान में चला जाता है, जिसके चलते राज्यों के पास बुनियादी ढांचे को खड़ा करने के लिए वित्तीय उपलब्धता कम रहती है। अब समय आ गया है कि केंद्र में आने वाली नई सरकार आर्थिक नीतियों के तहत इन राज्यों के लिए तीन बातों पर फोकस करे। पहली, इन राज्यों के नागरिकों तथा श्रमिकों में विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास किया जाए, ताकि उन्हें अच्छा रोजगार उपलब्ध हो। दूसरी, इन राज्यों की भौगोलिक संरचना के अनुसार जिन उद्योगों को यहां पर अधिक सफलता मिल सकती है, उनके लिए एक पूर्ण समर्पित आर्थिक नीति बनाई जाए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कि भारत के युवाओं को अपने स्टार्टअप्स को पूर्वोत्तर के इन राज्यों पर केंद्रित करने चाहिए तथा उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में इन राज्यों के विकास के संबंध में विशेष तौर पर उद्यमिता से संबंधित विशेष पाठ्यक्रम संचालित किए जाएं, ताकि युवा अपनी उद्यमिता के सफर के लिए इन राज्यों के प्रति अग्रसर हों।

भ्रष्टाचार पर वार कहीं राजनीतिक हथियार तो नहीं बन गया

राजकुमार सिंह

झारखंड में चंपई सोरेन सरकार द्वारा बहुमत साबित कर देने के बाद उन सवालों की गूंज और भी तेज सुनाई पड़ेगी, जो राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन द्वारा शपथ ग्रहण का न्यौता देने में दो दिन लगाने पर उठे थे। जबकि पड़ोसी बिहार में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने पांच घंटे में ही 'पालाबदल मुख्यमंत्री' नीतीश कुमार को पुन: शपथ दिलवा दी थी। मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद महागठबंधन विधायक दल का नेता चुने गए चंपई ने 47 विधायकों के लिखित समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा किया था। जब राज्यपाल ने विधायकों को मुलाकात का समय नहीं दिया, तब अपनी गिनती का वीडियो भी उन्होंने जारी किया, लेकिन राधाकृष्णन ने शपथ का न्यौता देने में दो दिन लगाए। हालांकि राज्यपाल ने 10 फरवरी तक का समय दिया था, लेकिन चंपई ने पांच फरवरी को ही बहुमत साबित कर दिया। चंपई सरकार को 47 मत ही मिले, जितने का दावा किया गया था। राज्यपालों की भूमिका पर सवाल देश में पहली बार नहीं उठे हैं। विडंबना है कि व्यवस्था परिवर्तन के वायदों के साथ होने वाले सत्ता परिवर्तनों से भी बदलता कुछ नहीं। स्वार्थ की खातिर दलबदल करनेवाले सफेदपोशों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। जिस विचारधारा की कभी बात होती थी, वह सत्ता की धारा में गुम हो चुकी है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्रीय सत्ता में अपनी 'हैट्रिक' सुनिश्चित करने के लिए भाजपा सरकार चुनाव से पहले ज्यादातर विपक्षी नेताओं को पीएमएलए कानून के तहत जेल भेज देना चाहती है, जिसमें जमानत आसान नहीं, क्योंकि जांच एजेंसी पर दोषसिद्धि के बजाय आरोपी पर ही खुद को निर्दोष सिद्ध करने की जिम्मेदारी होती है। पूरी व्यवस्था के लिए ही नासूर बन चुके भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए कठोरतम कानून की जरूरत से इनकार नहीं, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों को औजार बना कर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने की साजिश अगर मूल में है तो देश को भारी दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हेमंत के आदिवासी कार्ड समेत विपक्ष की इस पीड़ित मुद्रा का चुनाव में क्या प्रभाव होगा। यह तो परिणाम ही बताएंगे, लेकिन राजनेताओं के विरुद्ध दर्ज मामलों में 95 प्रतिशत विपक्षी नेताओं के विरुद्ध होने तथा दोषसिद्धि दर बहुत कम होने से केंद्रीय जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगते हैं। वैसे यूपीए शासनकाल में भी स्थितियां ज्यादा अलग नहीं थीं। विडंबना यह भी है कि विपक्ष अपने नेताओं के विरुद्ध आरोपों को तथ्यों के आधार पर गलत साबित करने के बजाय उन नेताओं के विरुद्ध जांच ठप पड़ जाने पर सवाल खड़े करता है, जो दल बदलते ही 'नेचुरली करप्ट' से 'मोस्ट फेवरिट' हो गए- और उस सवाल का जवाब कहीं से नहीं आता।

आरएलडी ने पलटीमार संकेत देकर इंडी गठबंधन की रीढ़ तोड़ दी

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में सियासत का पलड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकता नजर आ रहा है। यूपी का हाल यह है कि यहां बीजेपी को छोड़कर कोई भी दल लोकसभा चुनाव को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। विपक्षी दलों के नेता बीजेपी की बिछाई बिसात में फंसते जा रहे हैं। हालत यह है कि चुनाव सिर पर हैं, लेकिन कांग्रेस और बसपा चुनावी मैदान से नदारद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जमीनी हकीकत से दूर तंज कसने की राजनीति तक सिमट कर रह गये हैं। इंडी गठबंधन में दरार ही दरार नजर आ रही है। इसीलिए तो राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के नेता जयंत चौधरी भी इंडी से किनारा करते नजर आ रहे हैं। रालोद के विश्वास का हाल यह है कि उन्हें समझौते के तहत सपा से मिली सात सीटों की जगह बीजेपी से मिलने वाली चार सीटें ज्यादा लुभा रही हैं। हालाकि जयंत चौधरी और बीजेपी की तरफ से इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है, परंतु दोनों दलों ने इन खबरों का खंडन भी नहीं किया है। हां, समाजवादी पार्टी जरूर सफाई दे रही है कि उसके और रालोद का गठबंधन अटूट है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 लोकसभा सीटें राष्ट्रीय लोकदल को ऑफर की हैं। इनमें कैराना, मथुरा, बागपत और अमरोहा के नाम

शामिल हैं। राष्ट्रीय लोक दल इंडी गठबंधन के उन 28 दलों में शामिल था जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए तैयार था, लेकिन चुनाव की घोषणा भी नहीं हो पाई कि उससे पहले ही आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ने पलटी मार दी। उत्तर प्रदेश में साल 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने वाला राष्ट्रीय लोक दल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी से भी नाता तोड़ सकता है।

आरएलडी के एक बड़े नेता ने जानकारी दी कि आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन लगभग तय हो गया है। चार से पांच सीटें हर हाल में बीजेपी आरएलडी को दे रही है। हालांकि हमारी सात सीटों की मांग है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की मीटिंग भाजपा नेताओं के साथ जारी है। इस संबंध में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जयंत चौधरी बहुत पढ़े-लिखे नेता हैं। वह प्रदेश की खुशहाली और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के साथ नहीं जायेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने इन खबरों को पूरी तरह से अफवाह बताया और कहा कि सपा-रालोद का संबंध अटूट है।

कुल मिलाकर एक ओर प्रदेश में बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है, वहीं इंडी गठबंधन करीब-करीब पूरी तरह से बिखर गया है। कहने को तो फिलहाल सपा और कांग्रेस साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन यह साथ तभी तक बरकरार नजर आ रहा है, जब तक कांग्रेस सीटों के लिए मुंह नहीं खोल रही है। सपा ने कांग्रेस को 11 सीटों का आफर दिया है। यदि रालोद इंडी से अलग हो जाता है तो पश्चिमी यूपी में कांग्रेस को एक-दो सीटें और मिल सकती हैं। मगर इतनी सीटों पर भी जीत हासिल करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस ने यूपी में अभी तक चुनाव की तैयारी ही नहीं शुरू की है।

यूपी में इंडी गठबंधन क्यों बिखर रहा है, इसकी तह में जाया जाये तो सबसे बड़ा कसूरवार चेहरा राहुल गांधी ही नजर आते हैं। वैसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भूमिका भी सार्थक नजर नहीं आ रही है। अखिलेश जिस तरह से बसपा को इंडी गठबंधन से दूर रखने के लिए अड़ गये, वह भी किसी तरह से सही नहीं था। सबसे पहले बात राहुल गांधी की। यूपी में कभी कांग्रेस की तूती बोला करती थी, यूपी के सहारे ही कांग्रेस केन्द्र की सत्ता पर काबिज होती थी। यूपी गांधी परिवार का चुनावी गढ़ हुआ करता था। अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर जैसे जिलों में तो कांग्रेस को कोई टक्कर भी नहीं दे पाता था, लेकिन अब सब बदल चुका है। कांग्रेस के रणनीतिकार और गांधी परिवार के सदस्य राहुल गांधी यूपी छोड़कर जा चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से मिली करारी हार के बाद से राहुल ने मुड़कर यूपी की तरफ नहीं देखा।

समाजवादी पार्टी को भी माफ नहीं किया जा सकता है। जो पार्टी जनांदोलन से खड़ी हुई थी, अब वह सड़क पर लड़ते हुए नहीं दिखाई देती है। अखिलेश यादव अपने बयानों से सुर्खियां तो बटोरते रहते हैं, परंतु मतदाताओं से उनकी दूरी सपा के आगे बढ़ने के मार्ग में एक बड़ा अवरोध है। सपा की मुस्लिम तुष्टिकरण की सियासत भी सपा पर भारी पड़ती नजर आ रही है। खासकर जिस तरह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जिस तरह सपा ने दूरी बनाये रखी, वह सपा के पिछड़े और दलित वोटरों को भी रास नहीं आ रहा है क्योंकि राम सभी हिन्दुओं की आस्था से जुड़े हैं। पहले सपा ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाई।

यूपी, बिहार और उत्तराखंड के लिए भाजपा ने बनायी रणनीति

अजय कुमार

भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों से इत्तर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में अलग तरह से राजनैतिक पिच तैयार करने में लगी है। बीजेपी द्वारा उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने के लिए यूपी को भगवा कर दिया गया है। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की गूंज देश-विदेश सहित सियासी मोर्चों पर भी सुनाई दी तो वाराणसी के ज्ञानवापी तहखाने में जिला अदालत के आदेश के बाद पूजा अर्चना शुरू हो गई है। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का विवाद भी सरकार की इच्छाशक्ति के चलते जल्द सुलझता नजर आ रहा है। यह सब घटनाक्रम बीजेपी की मौजूदा राजनीति और चुनावी टाइमिंग के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। वैसे भी चुनावों के समय कौन-सा मुद्दा उठाना है और कौन-सा छोड़ना है, इसमें बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महारथ हासिल है। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तर प्रदेश विधान सभा के बजट सत्र के दौरान भी प्रभु श्रीराम का नाम खूब गूंजा। सत्ता पक्ष ने विधान सभा में श्रीराम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के लिये पीएम मोदी और सीएम योगी को बधाई संदेश देकर अयोध्या मुद्दे पर समाजवादी पार्टी में दो फाड़ ही कर दिये। समाजवादी पार्टी को प्रभु श्रीराम के मंदिर पर सियासत करना लोकतंत्र के मंदिर में उस समय भारी पड़ गया, जब सपा के विधायकों ने विधान सभा के भीतर हाथ उठाकर मोदी-योगी के लिए बधाई संदेश का समर्थन कर दिया। मात्र 14 विधायकों ने ही इसका विरोध किया। बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर भी बधाई संदेश का समर्थन करते दिखे। कुल मिलाकर बीजेपी और योगी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले यूपी को पूरी तरह से भगवामय कर देना चाहती है ताकि हिन्दू वोटरों को एकजुट किया जा सके। यदि ऐसा हो जाता है तो समाजवादी पार्टी सहित कांग्रेस और बसपा के लिये भी आम चुनाव चुनौती साबित हो सकते हैं। भाजपा अबकी से सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है।

2019 में हुए लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने बड़ी जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में एनडीए के घटक बीजेपी और अपना दल (एस) एक साथ मिलकर लड़े थे और एनडीए का 51.19 प्रतिशत वोट शेयर रहा था। जिसमें बीजेपी के खाते में 49.98 प्रतिशत और अपना दल (एस) को 1.21 प्रतिशत वोट शेयर मिला था। वहीं महगठबंधन (बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल) को 39.23 प्रतिशत वोट शेयर मिला था। जिसमें बसपा को 19.43 प्रतिशत, सपा को 18.11 प्रतिशत और रालोद को 1.69 प्रतिशत वोट मिला था। इसके अलावा कांग्रेस को इस चुनाव में 6.36 वोट शेयर मिला था। बात सीटों की कि जाये तो बीजेपी को 62, अपना दल (एस) को दो, बीएसपी को 10, सपा को पांच और कांग्रेस को एक सीट पर जीत हासिल हुई थी।

साल 2019 में हुए चुनाव के बाद यूपी की तीन सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें रामपुर, आजमगढ़ और मैनपुरी लोकसभा सीट शामिल रहीं। रामपुर में सपा नेता आजम खान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ था। आजम का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में बीजेपी ने उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। इसके अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई आजमगढ़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ। इस सीट पर सपा ने धर्मेंद्र यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था, वहीं बीजेपी ने इस सीट पर भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारा था। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को 8 हजार से अधिक वोटों से हराया था। वहीं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर भी उपचुनाव हुआ था। सपा का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में सपा की तरफ से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में थीं और इस सीट पर बीजेपी ने प्रेम सिंह शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया था।

हालांकि मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव ने जीत दर्ज की थी। अबकी से सपा और बसपा अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सपा का कांग्रेस से गठबंधन हो रखा है, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश की ही तरह उत्तराखंड भी भगवा रंग में रंगता जा रहा है। यहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के फैसलों से यह बात बार-बार साबित हो रही है। धामी सरकार द्वारा मदरसों की मनमानी पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं जगह-जगह बनाई गई मजारों को हटाया जा रहा है। उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य भी बन गया है, जिसने समान नागरिक संहिता को मंजूरी दे दी है। अब उत्तराखंड में सभी धर्मों के लड़के-लड़कियों की शादी की उम्र तय कर दी गई है। इसी तरह तलाक के मामले भी एक ही तरह से निपटाये जायेंगे। वहीं हलाला, बहुविवाह पर रो लगा दी गई है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में यूसीसी कानून के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के समान कानून होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों। वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा जनता से किए गए प्रमुख वादों में यूसीसी पर अधिनियम बनाकर उसे प्रदेश में लागू करना भी शामिल था। वैसे इसका विरोध भी शुरू हो गया है। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के कार्यकारी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि क्या इसके (यूसीसी) आने पर जितने भी कानून हैं उनमें एकरूपता आ जाएगी? नहीं, बिल्कुल एकरूपता नहीं होगी। जब आपने कुछ समुदायों को इससे छूट दे दी है तो एकरूपता कैसे हो सकती है? हमारी कानूनी समिति मसौदे का अध्ययन करेगी और उसके अनुसार निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री द्वारा 6 फरवरी को विधेयक पेश किये जाने के दौरान सत्तापक्ष के विधायकों ने ''भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्रीराम'' के नारे भी लगाये। गौरतलब हो कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने 04 फरवरी को यूसीसी मसौदे को स्वीकार करते हुए उसे विधेयक के रूप में सदन के पटल पर रखे जाने की मंजूरी दी थी। उधर, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार की मंशा पर संदेह है। उत्तराखंड में यूसीसी कानून बनने में कोई अड़चन नजर नहीं आ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड की पांचों सीटें जीती थीं। यहां इस बार भी बीजेपी के सामने कोई खास अड़चन नहीं दिखाई दे रही है।

बात बिहार की कि जाये तो यहां भी बदले सियासी माहौल में बीजेपी बढ़त में नजर आ रही है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से यूपी के साथ बिहार पहले से ही राममय था, अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें पिछड़ों का जनक कहा जाता है, को उनकी जन्म शताब्दी पर भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी ने हिंदी पट्टी के पिछड़ों और अति पिछड़ों को भी साध लिया है। कहते हैं, संसद का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर गुजरता है। दोनों ही राज्यों में पिछड़े और अति पिछड़े चुनावी गणित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

दरअसल, बिहार भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण राज्य है और यहां नीतीश कुमार कुछ-कुछ सालों में पाला बदलने का खेल खेलते रहते हैं। आज वह फिर से बीजेपी के साथ आ गये हैं, लेकिन उनका विश्वास नहीं लौटा है इसीलिए नरेंद्र मोदी की कोशिश यही है कि बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार को साथ रहते हुए भी अप्रासंगिक कर दिया जाए। वर्ष 2014 से इसके प्रयास भी वो लगातार करते आ रहे हैं। बिहार से लोकसभा की 40 सीटें हैं। वर्ष 2014 में जनता दल (यू), राजद और भाजपा, तीनों अलग-अलग चुनावी मैदान में उतरे थे। भाजपा के साथ रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जैसे छोटे दल थे। चुनाव में भाजपा ने सहयोगियों के साथ 40 में से 31 सीटों पर विजय हासिल की थी। जनता दल (यू) को दो और राजद को चार सीटें ही मिली थीं। इसके बाद नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ गए थे। वर्ष 2019 में उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन में रहते हुए बिहार में चुनाव लड़ा और लोकसभा की 16 सीटों पर विजय हासिल की। दोनों दलों के गठबंधन में राजद का सूपड़ा-साफ हो गया था और वो लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई थी।

हालांकि, इसके बाद नीतीश कुमार एक बार पलटी मार कर राजद के साथ चले गये थे, परंतु अब फिर बीजेपी के साथ आ गये हैं और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार भी चला रहे हैं। जहां तक हिंदी पट्टी के अन्य राज्यों- राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली और भाजपा के गढ़ गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, कर्नाटक व महाराष्ट्र की बात है तो इन सभी राज्यों में राम मंदिर का असर बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है। यह वोटों में तब्दील भी होगा, यह समय बतायेगा। इन राज्यों में लोकसभा की 222 सीटें हैं। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के असम समेत अन्य राज्यों में भाजपा की स्थिति मजबूत दिख रही है। वो यहां पुन: वर्ष 2019 वाला प्रदर्शन दोहरा सकती है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व ने भाजपा का वोट शेयर 31 प्रतिशत कर दिया और 282 सीटें पार्टी को मिलीं। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए ने 336 सीटों पर विजय हासिल की। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वोट शेयर को और बढ़ा दिया। यह बढ़कर 37.7 प्रतिशत हो गया और पार्टी ने अपने बलबूते पर 303 सीटों पर विजय हासिल की, यानी नरेंद्र मोदी जानते हैं कि जनता को क्या पसंद है और कैसे चुनाव-दर-चुनाव जीत हासिल करनी है।

छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल

भारत के ठीक मध्य में स्थित, छत्तीसगढ़ में पर्यटकों को आश्चर्यचकित करने के लिए बहुत कुछ है। स्वर्गीय झरनों, हरे–भरे अभयारण्यों, आश्चर्यजनक स्मारकों, आकर्षक शैल चित्रों से लेकर कई अन्य अनछुए परिदृश्यों तक, छत्तीसगढ़ में कई खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं जिनमें एक निर्विवाद आकर्षण है। भारत के धान के कटोरे के रूप में जाना जाने वाला, धान के खेतों का दृश्य एक और पर्यटक आकर्षण है जो लोगों को भारत के इस आश्चर्यजनक राज्य की यात्रा के लिए आकर्षित करता है। और अगर आप भी इस स्वर्ग जैसी जगह में कुछ मौज–मस्ती की तलाश में हैं, तो यहां घूमने के लिए बेहतरीन जगहों की सूची दी गई है। छत्तीसगढ़ जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा.

चित्रकोट जलप्रपात

छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में चित्रकोट जलप्रपात अनिवार्य रूप से सर्वोच्च स्थान का हकदार है। इसकी लोकेशन जगदलपुर से 50 किमी दूर है बस्तर जिला. इसे भारत के मिनी–नियाग्रा फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। चित्रकोट जलप्रपात इंद्रावती नदी से निकलता है जो विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है। घनी वनस्पतियों के बीच अपना रास्ता बनाते हुए, इस अद्भुत झरने का दृश्य आपको विशेषणों से बाहर कर देगा। आँखों के लिए सबसे अच्छा इलाज पाने के लिए, मानसून के मौसम के दौरान उस स्थान की यात्रा अवश्य करें जो जुलाई और अक्टूबर के बीच कहीं पड़ता है।

बरनवापारा वन्यजीव अभयारण्य

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 100 किमी की दूरी पर स्थित, बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य बार और नवापारा गाँवों का निवास स्थान है जो जंगलों से आच्छादित हैं। भारतीय बाइसन, गौर को देखने के लिए, इस जगह की यात्रा अवश्य करें। कभी–कभार नीची और ऊँची पहाड़ियों के साथ इसका सपाट भूभाग डॉट्स के रूप में दिखाई देता है जो इसकी सुंदरता को बढ़ाता है। यह भव्य पार्क लगभग 150 पक्षी प्रजातियों के साथ–साथ भौंकने वाले हिरणों की दिलचस्प विविधता का घर है जो आपकी यात्रा को रोमांचित कर देता है।

चंद्रहासिनी देवी मंदिर

छत्तीसगढ़ के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक, चंद्रहासिनी देवी मंदिर में माँ चंद्रहासिनी के कई भक्त आते हैं। यह पूजनीय मंदिर राज्य के जांजगीर–चांपा जिले में स्थित है। महानदी के तट पर स्थित, इस प्राचीन मंदिर में आठ हाथों वाली देवी को दर्शाया गया है रायगढ़ शहर.

बम्बलेश्वरी मंदिर

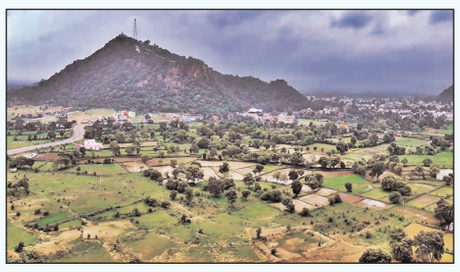

मां बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है जो इसे सबसे प्रसिद्ध उच्च पहाड़ी भारतीय मंदिरों में से एक बनाता है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र रोप–वे वहाँ स्थापित किया गया है जो पर्यटकों के लिए एक अन्य आकर्षण भी है।

दंतेश्वरी मंदिर

मां दंतेश्वरी को समर्पित दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा के जगदलपुर शहर से 84 किमी दूर है। मंदिर को बस्तर के राजाओं द्वारा बनवाए जाने और उनमें से एक होने के लिए मान्यता प्राप्त है भारत के 52 शक्ति पीठ. छत्तीसगढ़ के लोगों की दृष्टि में देवी दंतेश्वरी बस्तर राज्य की कुलदेवी हैं जो यहां के लोगों की शांति, शक्ति और स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं।

श्री राजीव लोचन मंदिर

भगवान विष्णु का पूजा स्थल, श्री राजीव लोचन मंदिर महाकोशल की

वास्तुकला को महत्वपूर्ण रूप से दर्शाता है। यह मंदिर 8वीं सदी में बना था और अब राजिम शहर में मौजूद है। इसमें भगवान नरसिंह, भगवान विष्णु, भगवान राम और देवी दुर्गा सहित कई देवी–देवताओं की नक्काशी वाले बारह स्तंभ हैं। यह तीन नदियों - महानदी नदी, सोंधू नदी और पेयरी नदी के संगम पर स्थित है। चैत्य मेहराबदार लकड़ी के रूपांकन इस मंदिर का आकर्षण हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार को नाग देवी की मूर्तियों से सजाया गया है जो आपकी आंखों को चकाचौंध कर सकती हैं।

कैलाश कुटुमसर गुफाएं

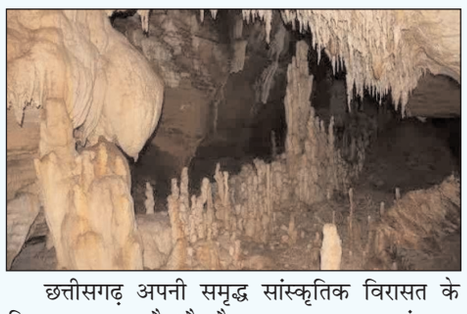

छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है और कैलाश कुटुमसर गुफाएं राज्य के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। ये गुफाएँ छत्तीसगढ़ के जगदलपुर नाम के एक छोटे से गाँव में स्थित हैं जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 35 किमी दूर है। इन गुफाओं की मनमोहक वास्तुकला पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती है। ये गुफाएँ निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक हैं जो हर यात्री की बकेट लिस्ट में होनी चाहिए।

भोरमदेव मंदिर

भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित एक हजार साल पुराना मंदिर है। यह मंदिर की चमकदार मूर्तियों के साथ बनाया गया है कोणार्क सूर्य मंदिर और खजुराहो मंदिर. यह धार्मिक स्थल भगवान शिव को समर्पित है। छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से विख्यात ईंटों के समूह के ये चार मंदिर अपनी शानदार सुंदरता से पर्यटकों का मन मोह लेते हैं।

सिरपुर विरासत स्थल

सिरपुर एक पुराना ऐतिहासिक स्थल है जो हिंदू धर्म की सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है। सिरपुर गांव महानदी के किनारे बसा है। यह गाँव देश के कुछ सबसे अच्छे ईंट मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है, जिनका नाम लक्ष्मण मंदिर और अन्य ईंट मंदिर हैं, गंधेश्वर मंदिर, राम मंदिर और बालेश्वर महादेव मंदिर हैं जो छत्तीसगढ़ में घूमने के लिए भी प्रसिद्ध स्थान हैं।

रायपुर शहर

जब हम किसी राज्य का दौरा करते हैं और उसकी राजधानी शहर को देखना भूल जाते हैं, खासकर जब आप छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हों तो यह पागलपन जैसा लगता है। इसकी राजधानी शहर रायपुर 9वीं शताब्दी से है और अतीत में इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और विभिन्न खोजकर्ताओं द्वारा इसका दौरा किया गया है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों में, यहाँ का प्रमुख आकर्षण महंत घासीदास मेमोरियल संग्रहालय है जिसमें विभिन्न जनजातियों के आदिवासी लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का एक शानदार संग्रह है। इसके अलावा, शहर दूधाधारी मठ और बूढ़ापारा झील का भी घर है। इस झील और मठ के निर्माण का श्रेय राजा ब्रह्मदेई को जाता है जिन्होंने इसे 1404 ईस्वी में बनवाया था। रायपुर के अन्य आश्चर्यजनक स्थलों में नंदनवन गार्डन, विवेकानंद सरोवर और हाजरा जलप्रपात शामिल हैं।

मैत्री बाग

जब आप प्रकृति के साथ एक आत्मीयता की तलाश कर रहे हैं, तो आपको मैत्री बाग
क ी

यात्रा अवश्य करनी चाहिए, जिसमें 111 एकड़ का पार्कलैंड है। यह भिलाई में स्थित एक चिड़ियाघर है जिसे फ्रेंडशिप गार्डन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना रूस और भारत की मित्रता के प्रतीक के रूप में 1972 में भिलाई स्टील पंप द्वारा की गई थी। यह स्थानीय लोगों के लिए एक मनोरंजक स्थल है जिसमें सकारात्मक ऊर्जा है। इसके अलावा, बगीचे में कई दिलचस्प गतिविधियाँ हैं जैसे नौका विहार, एक संगीतमय फव्वारा और साथ ही बैठने और आराम करने के लिए मैनीक्योर लॉन। कई वन्यजीव प्रजातियों का घर, इन प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने के लिए इस जगह की यात्रा अवश्य करनी चाहिए।

भूतेश्वर शिवलिंग

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक गांव मरौदा है जो विभिन्न मनोरम स्थलों के द्वार खोलता है। छत्तीसगढ़ में इस जगह का प्रमुख आकर्षण विशाल आकार का शिवलिंग है जो दुनिया में सबसे बड़ा है। जानने के लिए दिलचस्प तथ्य यह है कि हर गुजरते साल के साथ शिवलिंग की लंबाई 6 से 8 इंच बढ़ जाती है। यह 18 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा शिवलिंग हर साल लाखों भक्तों का मार्ग प्रशस्त करता है।

गड़िया पर्वत

कांकेर का सबसे ऊँचा पर्वत, गड़िया पर्वत अपने प्राकृतिक रूप में एक किला है। यह किला एक ऐसे टैंक के लिए जाना जाता है जिसमें साल भर पानी रहता है। अन्य यात्रा करने के लिए लोकप्रिय स्थान गड़िया पर्वत के चारों ओर शीतला मंदिर, शिवानी मंदिर और मालंझुकुडुम जलप्रपात हैं जो कि में स्थित हैं कांकेर सिटी.

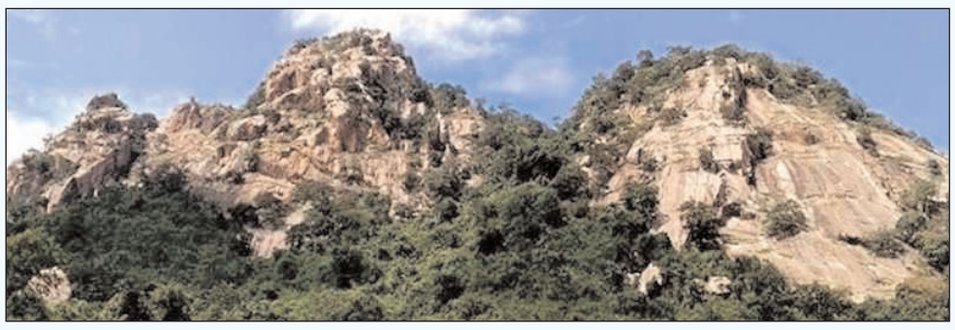

जम्मू-कश्मीर की इस मनमोहक जगह पर उठाएं ट्रेकिंग का आनंद

सर्दियों
के मौसम में हिल स्टेशन घूमना लोगों को काफी ज्यादा पसंद होता है। हिल स्टेशन के खूबसूरत नजारे और ठंडी हवाओं का अलग ही एहसास होता है। वैसे तो दिल्ली से उत्तराखंड और हिमाचल पहुंचना काफी ज्यादा आसान होता है। ऐसे में आप चाहें तो पार्टनर संग कश्मीर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बता दें कि हिमालय की गोद में बसे जम्मू–कश्मीर को भारत का जन्नत भी माना जाता है। यहां की हसीन वादियों के आप मुरीद हो जाएंगे। जम्मू–कश्मीर में बसी हर एक जगह की अपनी खासियत होती है। जिसको जीवन में एक बार जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए।

हांलाकि जम्मू–कश्मीर पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन अगर आप जम्मू–कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो एक बार आपको पहलगाम भी जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। बता दें कि पहलगाम में घास के मैदान, झील–झरने, बर्फ से ढके पहाड़ और दूध की तरह बहती नदी यहां की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं। वहीं बर्फबारी के दौरान इस जगह की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहलगाम में पर्यटकों की भारी भीड़ होती है।

बेताब वैली

पहलगाम में बेताब वैली को हजन वैली के नाम से भी जाना जाता है। यह पहलगाम से करीब 15 किमी की दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर कई फिल्मों को भी शूट किया जा चुका है। बताया जाता है कि साल 1983 में यहां पर फिल्म %बेताब% की शूटिंग की गई थी। यह जगह इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि फि ल्म का नाम इस जगह के नाम पर रख दिया गया। ऐसे में आपको यह जगह जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। इसके अलावा आप यहां पर ममलेश्वर मंदिर, शेषनाग झील और अरु वैली आदि जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।

चंदनवाड़ी

पहलगाम के बाहरी छोर पर स्थित चंदनवाड़ी वैली काफी ज्यादा मनमोहक है। पहलगाम से चंदनवाड़ी वैली की दूरी 15 किमी है। चंदनवाड़ी वैली म
झील–झरने और मनमोहक बर्फ से ढके पहाड़ आपका मन मोह लेंगे। काफी कपल्स यहां पर अपना हनीमून भी प्लान करते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में चंदनवाड़ी की खूबसूरती तो फेमस है। साथ ही इसका अपना धार्मिक महत्व भी है। इस स्थान से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। इसलिए सैलानियों के लिए यह जगह बेहद खास हो जाती है।

ममलेश्वर मंदिर

पहलगाम जाने के दौरान ममलेश्वर मंदिर जाना न भूलें। वैसे तो यहां पर आपको कई धार्मिक स्थल मिल जाएंगे। ममलेश्वर मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है। कोलाहोई ग्लेशियर से निकलने वाली एक जलधारा के पास यह मंदिर स्थित है। जो ममल गांव में स्थित है। पहलगाम से ममलेश्वर मंदिर की दूरी 1 किमी है।

अरु वैली

अगर आप ट्रेकिंग के शौकीन हैं, तो आपको अरु वैली जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। यहां पर आपको रुकने के लिए कई ऑप्शन मिल जाएंगे। ट्रेकिंग के दौरान जब आप पहाड़ों के बीच से निकलेंगे तो आपको कई खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप यहां पर पिकनिक मना सकते हैं। साथ ही पार्टनर के साथ सुकून के कुछ पल भी बिता सकते हैं।

बर्फ महोत्सव

अगर आपको भी बर्फ और ट्रेकिंग बेहद पसंद है। तो हर साल यहां पर होने वाले महोत्सव में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। यहां पर हर साल बर्फ महोत्सन आयोजित किया जाता है। इस दौरान आप यहां पर घुड़सवारी, स्कीइंग और स्पेलिंग जैसे एडवेंचर कर सकते हैं।

पहलगाम कैसे पहुंचें

पहलगाम पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले श्रीनगर जाना होगा। श्रीनगर से पहलगाम आप आराम से पहुंच सकते हैं। श्रीनगर आने के लिए आप बस, ट्रेन या फिर फ्लाइट से यात्रा कर सकते हैं। वहीं श्रीनगर पहुंचने के बाद आप टैक्सी से पहलगाम जा सकते हैं। श्रीनगर से पहलगाम की दूरी करीब 100 किमी के आसपास है।

सोलो ट्रिप का बना रहे प्लान तो चेन्नई में जरूर घूमें ये फेमस जगह

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई अपनी खूबसूरती के लिए देशभर में जाना जाता है। यहां पर कई हैरान करने वाले नजारे और स्वादिष्ट व्यंजन आपको बार–बार चेन्नई आने के लिए मजबूर करेंगे। कई लोग यहां पर दूर–दूर से अकेले ट्रेवल करने के लिए आते हैं। इसके साथ ही यहां पर महिलाएं भी बिना किसी टेंशन के अकेले यात्रा कर सकती हैं।

महिलाओं के लिए चेन्नई में यात्रा करना अब तक का सबसे अच्छा अनुभव साबित हो सकता है। ऐसे में अगर आप भी सोलो ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको चेन्नई की कुछ फेमस जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। जहां पर आपको घूमने का प्लान बनाना चाहिए।

महाबलीपुरम

अगर आप भी अकेले चेन्नई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आपको एक बार महाबलीपुरम को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। यह जगह चेन्नई से कुछ ही घंटों की दूरी पर है। महाबलीपुरम आने के लिए आपको सबसे पहले चेंगलपट्टू जिला आना होगा। यूनेस्को विश्व धरोहर में भी इस जगह का नाम शामिल है। प्राचीन चट्टानों को काटकर यहां मंदिर को बनाया गया है। इस मंदिर का शानदार नक्काशीदार मूर्तियां देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि इनको बेहद अनोखे तरीके से बनाकर तैयार किया गया है।

कांचीपुरम

वहीं चेन्नई के कांचीपुरम को मंदिरों के स्वर्ण शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर अकेले ट्रैवल करने वालों को सुकून का अनुभव होगा। अगर आप भी अकेले चेन्नई यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको एक बार कांचीपुरम जरूर आना चाहिए। कांचीपुरम का इतिहास पल्लव राजवंश से जुड़ा हुआ है। यह शहर फेमस मंदिरों और रेशम की साड़ियों के लिए जाना जाता है। यहां पर जाने के दौरान आपको एकाम्बरेश्वर मंदिर और कैलाशनाथ मंदिर जरूर जाना चाहिए। पारंपरिक दक्षिण भारतीय संस्कृति को एक्सपीरियंस करने के लिए आप लोकल मार्केट भी घूमने जा सकते हैं।

ब्रीज़ी बीच

ब्रीजी बीच उन लोगों के लिए बेस्ट हैं, जिन लोगों को समुद्र की शांत लहरों के पास बैठना पसंद होता है। अकेले चेन्नई यात्रा करने के दौरान आप ब्रीजी बीच जरूर जाएं। समुद्र की लहरों की मनमोहक आवाज और सनसेट देखना आपकी यात्रा की थकान को मिटाने का काम करेगा।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मुझे मोदी से मिलने के लिए पांच दिन में समय मिल गया

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि समझ नहीं आता कि कहां अन्याय हो रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जरूरत इस समय दिल्ली में ज्यादा है क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी हालिया मुलाकात के संदर्भ में कहा कि मुझे भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पांच दिन में ही समय मिल गया जबकि राहुल गांधी से मुलाकात के लिए मैं छह महीने से समय मांग रहा था मगर नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि राहुल गांधी सबसे व्यस्त नेता हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ लोग दो साल से राहुल गांधी से मिलने का समय मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि राहुल गांधी को लगता हो कि ऐसी मुलाकातों से समय बर्बाद होगा।

केरल सीएम के धरने में शामिल हुए केजरीवाल

नईदिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को राज्यों के लिए धन जारी करने में कथित भेदभाव को लेकर केंद्र के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर केरल के समकक्ष पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। केजरीवाल ने विरोध प्रदर्शन में कहा कि विपक्षी दल देश के 70 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी ने विपक्ष शासित राज्यों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। केंद्र सरकार विपक्षी सरकारों को परेशान करने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर भी मोदी सरकार की आलोचना की। केजरीवाल ने कहा कि ईडी अब एक नया हथियार है। अभी तक किसी व्यक्ति पर दोष साबित होने के बाद ही उसे जेल भेजा जाता था. लेकिन अभी उन्होंने (बीजेपी) तय ही किया है कि किसे जेल भेजना है।

कांग्रेस को झटका, असम में आप ने 3 उम्मीदवार उतारे

नईदिल्ली। इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख सदस्य द्वारा एक और एकतरफा घोषणा में, आम आदमी पार्टी (आप) ने गुरुवार को असम में तीन लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। आप के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने उम्मीद करते हुए तीन नामों की घोषणा की कि गठबंधन इन निर्वाचन क्षेत्रों से अनुमति देगा। मनोज धनोहर डिब्रूगढ़ से, भावेन चौधरी गुवाहाटी से और ऋषि राज सोनितपुर से आप के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पाठक ने इंडिया ब्लॉक के प्रति आप की प्रतिबद्धता पर जोर दिया लेकिन आसन्न चुनावों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हम एक परिपक्व और समझदार गठबंधन के भागीदार हैं और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय गुट इसे स्वीकार करेगा। लेकिन चुनाव जीतना सबसे महत्वपूर्ण है। हम इन तीन सीटों के लिए तुरंत तैयारी शुरू कर रहे हैं। पाठक ने गठबंधन सहयोगियों से बातचीत की प्रक्रिया में तेजी लाने और अभियान की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने का भी आग्रह किया।

जीत उसी की होगी जिसके पक्ष में भगवान हैं : अखिलेश यादव

लखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के तीन जगहों की मांग वाले बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीएम संविधान से बंधे हैं। उन्हें ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जो सीएम के तौर पर ली गई उनकी शपथ के मुताबिक न हो। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कौरव कौन हैं और पांडव कौन हैं। कौरव संख्या में अधिक थे... बीजेपी कहती है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमने महाभारत में पढ़ा है कि जिनके पास सबसे बड़ी सेना थी कौरव... जीत उसी की होगी जिसके पक्ष में भगवान हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और सपा-कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर अखिलेश ने कहा कि जब यात्रा यहां होगी तो जो भी होगा सब देखेंगे... गठबंधन जीत के आधार पर होगा... हम जल्द ही पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा उम्मीदवार जारी करेंगे।

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया

मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने लगभग पांच दशकों तक पार्टी का सदस्य रहने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। सिद्दीकी मुंबई में कांग्रेस के एक प्रमुख अल्पसंख्यक चेहरा थे जो कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की गठबंधन सरकार के समय मंत्री भी थे। पूर्व मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं एक युवा के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ और यह 48 वर्षों तक चलने वाली एक महत्वपूर्ण यात्रा रही है। आज मैं तत्काल प्रभाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा, बहुत कुछ है जिसे मैं व्यक्त करना चाहता हूं लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि कुछ चीजों को अनकहा छोड़ देना ही बेहतर है। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जो इस यात्रा में हिस्सा रहें।

कांग्रेस ने मोदी सरकार की 'विफलताओं' के खिलाफ जारी किया 'ब्लैक पेपर'

खड़गे बोले- देश में लोकतंत्र को खत्म कर रही भाजपा

नईदिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को केंद्र के बहुचर्चित श्वेत पत्र के खिलाफ काला पत्र जारी किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद के मौजूदा बजट सत्र के दौरान सरकार का श्वेत पत्र पेश करने की उम्मीद है। खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज हम सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर ला रहे हैं। पीएम (नरेंद्र) मोदी जब भी संसद में अपने विचार रखते हैं, तो अपनी विफलताओं को छिपाते हैं। वहीं, जब हम सरकार की विफलताओं के बारे में बात करते हैं तो उसे महत्व नहीं दिया जाता। इसलिए हम ब्लैक पेपर निकालकर जनता को सरकार की नाकामियों के बारे में बताना चाहते हैं।

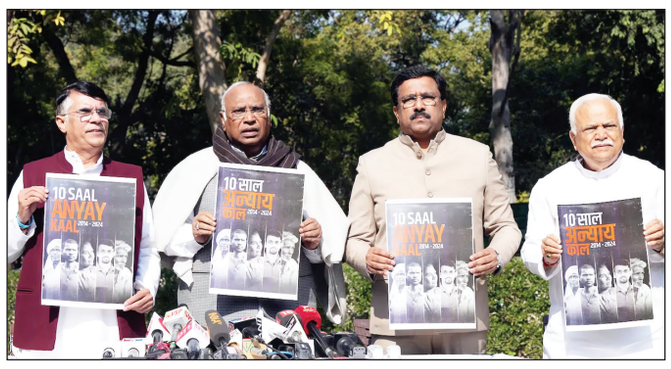

रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कांग्रेस का ब्लैक पेपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 10 साल के शासन कार्यकाल पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे गैर-बीजेपी राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है...। खड़गे ने कहा, ब्लैक पेपर बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और किसानों के संकट के संबंध में नरेंद्र मोदी सरकार की विफलताओं को उजागर करता है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने देश की आजादी सुनिश्चित की और 2024 में वह देश को भाजपा के अन्याय के अंधेरे से बाहर निकालेगी।

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा, देश में लोकतंत्र को खतरा है...बीते 10 साल में 411 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है। उन्होंने कांग्रेस की कई सरकारें गिरा दीं। वे लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। एक श्वेत पत्र एक सरकारी प्रकाशन के रूप में कार्य करता है जिसे नई नीतियों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य जनता का समर्थन हासिल करना और प्रतिक्रियाओं का आकलन करना है। आमतौर पर, यह अपने सफेद आवरण से पहचाना जाता है।

उन्होंने दावा किया कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, लेकिन मोदी सरकार इसकी बात कभी नहीं करती। खरगे ने कहा कि सरकार हमेशा अपने 10 साल के कार्यकाल की तुलना संप्रग सरकार से करती है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में कभी नहीं बताती। उन्होंने सरकार पर विपक्षी पार्टियों के शासन वाले राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया।

खरगे ने कहा, ''जिस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है, केंद्र सरकार वहां मनरेगा का पैसा भी नहीं देती, फिर बाद में कहती है कि पैसा तो रिलीज हुआ, लेकिन वो खर्च नहीं किया गया।''कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ''देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उसे कम करने के बदले कांग्रेस से तुलना करते रहते हैं। मोदी सरकार चाहे तो दाल, तेल समेत रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर महंगाई को नियंत्रित कर सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए बाहर से चीजें आयात कराते हैं।''

खरगे ने सरकार पर रोजगार के मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया और कहा, ''दो करोड़ नौकरियों देना, किसानों को एमएसपी सुनिश्चित करना मोदी की गारंटी थी। वह इन्हें पूरा नहीं कर सके और अब नई गारंटी लेकर आ गए हैं।''

राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों की विदाई के अवसर पर उच्च सदन को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया

कांग्रेस का ब्लैक पेपर हमारी 10 साल की उपलब्धियों का काला टीका है : मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एनडीए सरकार के कार्यकाल के खिलाफ जारी किए गए ब्लैक पेपर को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह 10 वर्षों में हमारी उपलब्धि के लिए काला टीका की तरह है। कांग्रेस ने आज पहले मोदी सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए एक ब्लैक पेपर जारी किया, जिसमें बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और किसान संकट जैसे मुद्दों को उठाया गया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा 10 साल अन्य काल शीर्षक से ब्लैक पेपर का विमोचन सरकार द्वारा 2014 से पहले अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन पर एक श्वेत पत्र संसद में पेश करने से पहले किया गया है, जिसका उद्देश्य ध्यान आकर्षित करना है। ब्लैक पेपर बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, किसानों की परेशानी, जाति जनगणना करने में विफलता और महिलाओं के साथ अन्याय जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए खड़गे ने महंगाई के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वह जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की बात करते हैं लेकिन वे अब शासन कर रहे हैं और उन्हें जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। 2 करोड़ नौकरियाँ प्रदान करना और किसानों को एमएसपी सुनिश्चित करना मोदी की गारंटी थी और अब प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि वह ऐसा नहीं कर सके, लेकिन इसके बजाय वह नई गारंटी लेकर आए हैं।

खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने भारत की आजादी सुनिश्चित की और 2024 में वह देश को भाजपा के अन्याय के अंधेरे से बाहर निकालेगी। प्रधानमंत्री राज्यसभा में उन संसद सदस्यों (सांसदों) को शुभकामनाएं देने के लिए बोल रहे थे जिनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है और उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि एक सांसद के रूप में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है।

जब भी लोकतंत्र की चर्चा होगी मनमोहन सिंह के योगदान को याद किया जाएगा : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को देश के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के योगदान की सराहना की और कहा कि जब भी लोकतंत्र की चर्चा होगी तो उनके योगदान को याद किया जाएगा। राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों की विदाई के अवसर पर उच्च सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद सदन की कार्यवाही में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मनमोहन सिंह की सराहना की और उनके दीर्घायु होने की भी कामना की। मनमोहन सिंह सहित उच्च सदन के 68 सदस्य फरवरी से मई महीने के बीच सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''इस अवसर पर मैं विशेष रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मरण करना चाहूंगा। वह छह बार इस सदन के सदस्य रहे। वह अपने मूल्यवान विचारों से सदन की चर्चाओं को समृद्ध करते रहे। सदन के नेता के रूप में तथा प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।'' मोदी ने कहा कि वैचारिक मतभेदों के कारण कभी बहस के दौरान छींटाकशी हो जाती है लेकिन वह बहुत अल्पकालीन होता है। उन्होंने कहा, ''लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है... देश का मार्गदर्शन किया है...वह हमेशा...जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी... कुछ माननीय सदस्यों की चर्चा होगी... उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान की चर्चा जरूर होगी।''

प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी सदस्य इस सदन में आता है, वह चाहे किसी भी दल का क्यों न हो, अपने कार्यकाल के दौरान वह अपनी प्रतिभा और व्यवहार के दर्शन जरूर कराता है। उन्होंने कहा कि ऐसे सदस्यों के कार्यकाल से मार्गदर्शक के रूप में सीखने का प्रयास होना चाहिए। सदन और विभिन्न समितियों में मतदान के अवसर पर मनमोहन सिंह की भागीदारी को याद करते हुए मोदी ने कहा कि वह इन अवसरों पर भी व्हीलचेयर पर आए और लोकतंत्र के प्रति भागीदारी सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि सभी को पता था कि विजय सत्ताधारी पक्ष की होने वाली है लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हीलचेयर में आए और उन्होंने मतदान किया।

उन्होंने कहा, ''एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, उसका वह उदाहरण है। वह प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कि कभी कमेटी सदस्यों के चुनाव हुए तो भी वह व्हीलचेयर में वोट देने आए। सवाल यह नहीं है कि वह किसको ताकत देने के लिए आए थे... मैं मानता हूं वह लोकतंत्र को ताकत देने आए थे।'' उन्होंने मनमोहन सिंह के दीर्घायु होने की कामना की और कहा कि वह निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते रहें और हमें प्रेरणा देते रहें। मनमोहन सिंह देश के चौदहवें प्रधानमंत्री थे। वर्ष 2004 से 2014 तक वह देश के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निर्धारण में उनकी भूमिका की आज भी सराहना होती है।

खेल
प्रमुख समाचार

विश्व कप में सफलता की कुंजी होंगे बुमराह

नईदिल्ली। सभी प्रारूपों में जसप्रीत बुमराह के हालिया प्रदर्शन से प्रभावित दक्षिण अफ्रीका के पूर्व मध्यम तेज गेंदबाज वेर्नोन फिलेंडर ने कहा है कि वह इस साल होने वाले टी20 विश्व कप में भारत की सफलता की कुंजी रहने के साथ सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज भी साबित होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम में दूसरे टेस्ट में नौ विकेट लेकर भारत को 91 रन से जीत दिलाकर सीरीज में 1-1 से वापसी कराने वाले बुमराह आईसीसी टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले कपिल देव दिसंबर 1979 से फरवरी 1980 के बीच दूसरे नंबर पर पहुंचे थे। फिलैंडर ने कहा ,'बुमराह इस समय मुकम्मिल गेंदबाज है। उनके पास जबर्दस्त कौशल है और उन्होंने सटीक गेंदबाजी का हुनर सीख लिया है, जिससे टेस्ट क्रिकेट में इतनी सफलता मिल रही है। पहले वह हर समय विकेट लेने वाली गेंद फेंकना चाहते थे जिससे महंगे साबित होते थे लेकिन अब उनके प्रदर्शन में निरंतरता है।'

उन्होंने कहा ,'' वह ऐसे गेंदबाज हैं जिन्हें टी20 क्रिकेट में भी कभी कमतर नहीं आंका जा सकता। वह नयी गेंद से स्विंग कराते हैं और बल्लेबाज को आगे बढ़कर खेलने के लिये मजबूर करते हैं। उनके यॉर्कर काफी धारदार होते हैं और टी20 क्रिकेट में यही तो चाहिये। मुझे लगता है कि वह टी20 विश्व कप में सबसे कामयाब तेज गेंदबाज होंगे ।'' टी20 विश्व कप जून में वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेला जायेगा। उन्होंने मोहम्मद शमी की भी तारीफ करते हुए कहा कि वह गेंद को बखूबी स्विंग कराते हैं । दक्षिण अफ्रीका के लिये 64 टेस्ट में 224 विकेट लेने वाले इस गेंदबाज ने कहा ,'' भारत के मौजूदा तेज गेंदबाजों से मैं काफी प्रभावित हूं । बुमराह के अलावा मोहम्मद शमी भी हैं जो सीम का बखूबी इस्तेमाल करते हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 724 अंक लुढ़का निफ्टी 21,718 पर बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दर्ज की गई और बीएसई सेंसेक्स 700 से ज्यादा अंक की गिरावट लेकर बंद हुआ। इंडेक्स में हैवी वेटेज रखने वाली आईटीसी के शेयरों में फिसलन और आरबीआई के रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखने के फैसले के बाद प्राइवेट बैंकों के शेयरों में आई गिरावट से बाजार गिरकर बंद हुआ। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज करीब 300 अंक की बढ़त लेकर 72,473.42 पर खुला। हालांकि, सेंसेक्स ज्यादा देर तक हरे निशान में नहीं रह सका और कुछ देर में गिरावट में चला गया। अंत में यह 1.00 प्रतिशत या 723.57 अंक गिरकर 71,428.43 के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 0.97 प्रतिशत या 212.55 अंक की गिरावट के साथ 21,717.95 के स्तर पर बंद हुआ।

आरबीआई एमपीसी ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति मुंबई में मंगलवार को शुरू हुई तीन दिवसीय बैठक के बाद 8 फरवरी को रेपो दरों पर अपने फैसले का खुलासा किया। गुरुवार सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास एमपीसी के फैसले का ऐलान किया। आरबीआई एमपीसी ने फरवरी 2024 तक लगातार छठी बार रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर बनाए रखा है। बेंचमार्क ब्याज़ दर को पिछली बार फरवरी 2023 में बढ़ाया गया था, उस समय इसे 6.25 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्तमान 6.5 प्रतिशत कर दिया गया था। इससे पहले, इसने मई 2022 से फरवरी 2023 तक रेपो दर में 250 आधार अंकों की वृद्धि की गई थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस बार की बैठक में विस्तार से चर्चा के बाद एमपीसी ने फैसला किया है कि रेपो रेट को अभी 6.5% पर ही स्थिर रखा जाए। छह में से पांच सदस्य इसके समर्थन में रहे।

गौतम अदाणी फिर 100 अरब डॉलर वाले क्लब में शामिल

नईदिल्ली। अदाणी ग्रुप के मालिक गौतम अदाणी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के एक साल बाद 100 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति वाले लोगों के एलीट क्लब में एक बार फिर शामिल हो गए हैं। गौतम अदाणी की टोटल नेटवर्थ बुधवार को 2.7 बिलियन डॉलर बढ़कर 100.7 बिलियन डॉलर हो गई। अदाणी की यह संपत्ति शार्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से ग्रुप पर बाजार में हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप लगाने के बाद से सबसे ज्यादा है। अदाणी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयरों में पिछले हफ्ते जारी तिमाही नतीजों के बाद बुधवार को आठवें दिन तेजी आई। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, गौतम अदाणी अब दुनिया के 12वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अपने हमवतन मुकेश अंबानी से सिर्फ एक स्थान पीछे हैं।

जनवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश हुआ दोगुना

नईदिल्ली। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जनवरी, 2024 में शुद्ध रूप से 21,780 करोड़ रुपये का निवेश आया है। यह लगभग दो साल में किसी भी महीने में हुआ सबसे अधिक मासिक निवेश है। इस दौरान निवेशकों ने स्मॉल-कैप फंड को प्राथमिकता देना जारी रखा। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। दिसंबर, 2023 में इस श्रेणी में लगभग 17,000 करोड़ रुपये का निवेश आया था। जनवरी में निवेश प्रवाह मार्च, 2022 के बाद से सबसे अधिक था। मार्च, 2022 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 28,463 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि इक्विटी फंडों में लगातार 35 माह से शुद्ध निवेश आ रहा है। समीक्षाधीन महीने में वैल्यू फंड को छोड़कर, इक्विटी खंड की सभी श्रेणियों में शुद्ध प्रवाह आया।

अचानक अंतरिक्ष में क्यों भेजे जा रहे हैं इतने मिशन्स?

संकल्प सिंह

अचानक इस दशक के शुरू होते ही ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका, चीन, रूस और हमारा देश भारत चांद पर जाने के लिए कई स्ट्रैटेजिक मिशन्स प्लान कर रहा है। अमेरिका तो अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए साल 2026 में दोबारा इंसानों को चांद पर उतारने जा रहा है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इन मिशन्स के जरिए वैज्ञानिक खोजें, रिसर्च और स्पेस एक्स्प्लोरेशन किया जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। इन सब से कहीं ज्यादा इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल छिपा है। आने वाले भविष्य में चांद एक बहुत बड़ा सेलेस्टियल चॉक पॉइंट बनने जा रहा है, जो स्पेस रेस और मॉडर्न वारफेयर की परिभाषा को ही बदल के रख देगा।

साल 2019 में नाटो स्पेस को एक ऑपरेशनल डोमेन डिक्लेअर करता है। इस निर्णय के ठीक बाद अमेरिका दुनिया की पहली डेडिकेटेड स्पेस फोर्स को लॉन्च करता है। यही नहीं फ्रांस इसके बाद अपनी एयर फोर्स का नाम बदलकर एयर एंड स्पेस फोर्स कर देता है। इनके साथ-साथ दुनिया की स्पेस प्रोग्राम रन करने वाले कई देश भी इस निर्णय के ठीक बाद स्पेस में अपने वर्चस्व को लेकर कई रणनीतिक कदम उठाते हैं।

आप समझ रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है? स्पेस शायद अब एक नया जंग का मैदान बनने जा रहा है। स्पेस रेस का उद्देश्य अब वैज्ञानिक खोजों और स्पेस एक्सप्लोरेशन से कहीं ज्यादा युद्ध जैसी परिस्थितियों में स्पेस के मेजर चॉक पॉइंट्स पर अपना वर्चस्व स्थापित करना है। इसी को देखते हुए रूस और चीन अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। वहीं हमारा भारत भी इसमें पीछे नहीं है।

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का बेसिक मॉडल साल 2028 तक धरती ऑर्बिट में सेट कर दिया जाएगा। वहीं इसे पूरा बनाने का लक्ष्य साल 2035 तक रखा गया है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर स्पेस कैसे वॉर का एक नया फ्रंटियर बन रहा है? स्पेस तो अंतहीन है। फिर यहां पर लड़ाई करके दुनिया को क्या मिलेगा। आइए समझते हैं इसे विस्तार से –

अगर वॉर के ट्रेंड को देखेंगे, तो शुरुआत में लड़ाई जमीन को लेकर होती थी। उसके बाद ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने महासागरों का इस्तेमाल करके बड़े-बड़े जहाजों के जरिए दुनियाभर में शासन किया। इसके बाद दोनों विश्व युद्ध में एयर एक नया वॉर का फ्रंटियर बन कर उभरा, जब बड़े बड़े एयरक्राफ्ट के जरिए एक देश दूसरे देशों के स्ट्रैटेजिक पॉइंट पर हमला कर रहे थे। जापान द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर पर किया गया ऐतिहासिक हमला इनमें से एक था।

अब हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां साइबर स्पेस और स्पेस, वारफेयर के एक नए फ्रंटियर के रूप में उभर रहे हैं। अमेरिका को यह पता है कि जिस तरह फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने ओसियंस को कैपिटलाइज करके दुनियाभर में अपना शासन किया था। ठीक उसी तरह अगर स्पेस को कैपिटालाइज कर लिया जाए, तो पूरी दुनिया पर अपनी बादशाहत बनाई जा सकती है। और ये बात रूस, चीन के साथ साथ हमारा देश भारत भी जानता है।

हमारे पृथ्वी के आसपास ऐसे कई जरूरी चॉक पॉइंट्स हैं, जहां पर अगर कोई देश कंट्रोल पा ले, तो उस देश को 21वीं सदी के स्पेस रेस में पीछे करना काफी मुश्किल है। इसमें पहली कैटेगरी में अर्थ के तीनों ऑर्बिट जोन्स, लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट शामिल हैं। इन तीनों ऑर्बिट में सैटेलाइट को उनकी जरूरतों को देखकर इंस्टॉल किया जाता है। यही सैटेलाइट दुनियाभर में इंटरनेट, कम्यूनिकेशन, जीपीएस, अर्थ की ऑब्जर्वेशन, वेदर फॉरकास्टिंग से लेकर स्पाई और सर्विलांस करने के लिए इस्तेमाल में आ रहे हैं। विश्व के कई देश इन सैटेलाइट कम्यूनिकेशन नेटवर्क पर आश्रित हैं। और हमारा इंडिया भी इनमें से एक है।

आज के समय कई जरूरी सी रूट्स जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, मलक्का स्ट्रेट, स्वेज कैनाल ग्लोबल इकोनॉमी को पम्प करने में एक इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक इसी तरह धरती के ऑर्बिट जोन में मौजूद ये सैटेलाइटें भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ईंधन की भूमिका निभा रही हैं।

स्वामी आत्मानंद स्कूलों की संचालन समितियां होगी समाप्तःअग्रवाल

स्वामी आत्मानंद स्कूल अब शिक्षा विभाग के जिम्मे

आर.डी. तिवारी स्कूल मरम्मत में अनियमितता की होगी जांच

रायपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की महान विभूति, शिक्षाविद् और समाज सुधारक और जन जागरण के पुरोधा स्वामी आत्मानंद जी के नाम पर तत्कालीन सरकार ने राज्य भर में अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम उत्कृष्ट स्कूल खोल कर न सिर्फ शिक्षा और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, बल्कि स्वामी आत्मानंद जी के नाम को भी धूमिल किया है। इन स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के जिम्मे सौंप कर तत्कालीन सरकार ने इसका भविष्य कलेक्टरों की इच्छा पर सौंप दिया है। यह राज्य की शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षा की वर्तमान स्थिति, अनियमितता और कुप्रबंधन को देखते हुए हमारी सरकार ने इसके संचालन के लिए कलेक्टरों की अध्यक्षता में गठित समितियों को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षा-दीक्षा की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अब शिक्षा विभाग की होगी।

शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल आज विधानसभा में स्वामी आत्मानंद स्कूलों के कुप्रबंधन एवं वहां व्याप्त अनियमितता के संबंध में ध्यानाकर्षण का जवाब देने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उक्त बातें कही। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि स्वामी आत्मानंद पूरे देश में पूज्यनीय हैं। हम सभी के मन में उनके लिए सम्मान है। पहले ये स्कूल जिन महान हस्तियों के नाम से जाने जाते थे, उनका नाम फिर से स्वामी आत्मानंद से पहले जोड़ा जाएगा।

मंत्री श्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूलों को लेकर अगर कोई अनियमितता की शिकायत मिलती है, तो उसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वामी आत्मानंद स्कूलों के पुनर्निर्माण और अन्य मदों में लगभग 800 करोड़ रुपए घोटाले की आशंका है। जहां भी शिकायत प्राप्त होगी, उसकी जांच

कराई जाएगी। अकेले राजधानी रायपुर के आर.डी. तिवारी स्कूल में ही लगभग 4.5 करोड़ रुपए बिल्डिंग मरम्मत पर खर्च किए गए, जबकि इतनी राशि में एक नई बिल्डिंग का निर्माण हो जाता।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छत्तीसगढ़ में हुआ भव्य स्वागत

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा 26वें दिन छत्तीसगढ़ पहुंची। इस दौरान उड़ीसा छत्तीसगढ़ सीमा में ध्वज हस्तांतरण समारोह संपन्न हुआ। उड़ीसा कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शरद पटनायक ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज को राष्ट्रध्वज सौंपे।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छत्तीसगढ़ में भव्य स्वागत हुआ। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता और आम जनता राहुल गांधी को सुनने के लिए इकट्ठा हुए। ध्वज हस्तांतरण के पश्चात भारत जोड़ो न्याय यात्रा की 2 दिन का विश्राम होगा। विश्राम के पश्चात पुनः भारत जोड़ो न्याय यात्रा 11 फरवरी को रायगढ़ से शुरू होगी जिसका समापन 14 फरवरी को अंबिकापुर में होगा।

बीजेपी की जीत की तैयारी ! चुनाव समिति की बैठक में बनी लोकसभा चुनाव की रणनीति

11 में से 11 सीट जीतें यह तय हुआः किरणदेव

रायपुर. लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है. चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई. बैठक के बाद

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह का बयान सामने आया है. उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से बैठक हुई. कार्य योजना को कैसे क्रियान्वित करना है और कौन-कौन से कार्यक्रम किया जाना है इन सभी विषयों पर चर्चा हुई. आगे उन्होंने कहा, पीएम मोदी के चेहरे की बात स्वभाविक है. विश्व के मानचित्र पर भी देखें तो पीएम मोदी बड़े नेता हैं. जीत का मापदंड सबसे बड़ा विषय होगा. 11 में से 11 सीट जीतें यह तय हुआ है. वहीं नामों के पैनल को लेकर कहा, संयोजन किया जाना है. आगे आप सभी को पता चलेगा. बता दें कि, भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में हुई. इस बैठक में सह प्रभारी नितिन नबीन, सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत वरिष्ठ नेता मौजूद थे.

भारत जोड़ो न्याय यात्रा

पिछली यात्रा के बाद कांग्रेस तीन राज्यों से बेदखल हुई थी

रायपुर. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कांग्रेस की फिजूल सियासी कवायद करार देते हुए तंज कसा है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के इस राजनीतिक प्रहसन को प्रदेश की जनता ने कतई रिस्पॉन्स नहीं दिया है. तमाम संसाधन झोंकने के बाद भी कांग्रेस अपने 'शहजादा' को स्थापित करने में विफल साबित हुई है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की पिछली भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस तीन राज्यों की सत्ता से बेदखल हुई थी. अबकी बार तो छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी. उन्होंने कहा कि अन्याय की पराकाष्ठा करने वाली कांग्रेस अब किस मुंह से न्याय यात्रा के नाम

पर गाल बजा रही है? भाजपा मानती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस का एक और सुपर फ्लॉप शो साबित होगी और इसका कोई राजनीतिक लाभ कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है. छत्तीसगढ़ की जनता ने हाल के विधानसभा चुनाव में 'मोदी की गारंटी' पर भरोसा जताकर भाजपा को जो ऐतिहासिक जनादेश देकर सत्ता सौंपी है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में इस यात्रा के बाद भी कांग्रेस को एक लोकसभा सीट भी नहीं मिलने वाली है. उन्होंने आगे कहा कि दरअसल कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पा रही है. कांग्रेस मोदी-विरोध के एजेंडे पर चलते-चलते अब देश और देश की जनता का विरोध करने लगी है. जिसे देश की जनता स्वीकार नहीं कर रही है.

मोदी की हर गारंटी को पूरा करेंगेः साय

विधानसभा में राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन पारित

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा बजट सत्र के शुभारंभ के अवसर पर दिए गए अभिभाषण पर आज चर्चा के बाद राज्यपाल महोदय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्यपाल महोदय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि हमने प्रदेश में सुशासन की स्थापना का संकल्प लिया है। हम छत्तीसगढ़ की जनता के जीवन में खुशहाली और समृद्ध लाने के लिए मोदी जी हर गारंटी को पूरा करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता जीर्ण-शीर्ण हो चुके प्रदेश के वित्तीय-ढांचे को फिर से मजबूत करने और फिर से कुशल वित्तीय प्रबंधन की स्थापना करने की होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने हमें विरासत में खाली खजाना और भारी कर्ज सौंपा है। अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संसाधनों का इंतजाम हमारे सामने बड़ी चुनौती हो सकती थी, लेकिन जनता-जनार्दन के आशीर्वाद, विश्वास, समर्थन और सहयोग से ऐसी तमाम तरह की चुनौतियों पर विजय पाने में हम कामयाब हो रहे हैं।

माओवादी आतंक प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से बुनियादी सुविधाओं की पहुंच करेंगे सुनिश्चित

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का फोकस किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं पर रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए जो गारंटियां दी हैं, उनका फोकस भी मुख्य रूप से इन्हीं वर्गों पर है। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी करना, सामाजिक और भौतिक विकास में तेजी लाने के लिए अधोसंरचनाओं का निर्माण करना, शिक्षा, चिकित्सा, संस्कृति, संस्कार, रोजगार, व्यापार जैसे क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ राज्य सरकार काम करेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं और नीतियों का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि नवा रायपुर में मध्यभारत इनोवेशन हब बनाने की दिशा में तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस इनोवेशन हब के जरिए लाखों की संख्या में रोजगार के नये अवसरों का निर्माण होगा।

देश का पहला सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज छत्तीसगढ़ में

सौर ऊर्जा का यह उत्कृष्ट मॉडल जिला राजनांदगांव में है स्थापित

रायपुर। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ रोड पर ग्राम ढ़ाबा के आस-पास के 4-5 गांव के पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। संयंत्र के साथ स्थापित बैटरी सिस्टम के माध्यम से रात्रि में भी बिजली प्रदाय की सुविधा रहेगी। इससे प्रतिदिन 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा और लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, इससे हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। क्रेडा द्वारा राजनांदगांव में ऑनग्रिड सोलर पावर प्लांट स्थापना का कार्य सोलर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) एवं छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सौंपा गया। इस कंपनी द्वारा 01 फरवरी 2024 को संयंत्र स्थापना कार्य पूर्ण कर कार्यशील किया गया। यह देश का पहला ऑनग्रिड सोलर सिस्टम है, जिसमें 100 मेगावॉट का सोलर संयंत्र स्थापित किया गया है। इस प्लांट की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें 660 वॉट क्षमता के कुल 2 लाख 39 हजार बाईफेसियल सोलर पैनल स्थापित किये गये हैं, जिससे पैनल के दोनों ओर से प्राप्त सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली का निर्माण किया जा रहा है। इसकी कुल परियोजना लागत 960 करोड़ रूपये हैं, जो कि सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन कर आगामी सात वर्षों तक प्राप्त हो जाएगी। इस पार्क के माध्यम से प्रति दिन लगभग 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आ रही है एवं हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिल रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यह परियोजना देश एवं प्रदेश में उत्कृष्ट मॉडल के रूप में देखा जाएगा। साथ ही ऐसे अनेक परियोजनाओं पर क्रेडा द्वारा कार्य किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ शासन द्वारा राजनांदगांव जिले के बैरन पहाड़ी क्षेत्र के उत्तम उपयोग के दृष्टिकोण से देश एवं प्रदेश के प्रथम सोलर पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया। शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रारंभ वर्ष 2016 में हुआ। इसके तहत् ग्रिड कनेक्टेड मेगा साईज सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के द्वारा दो चरणों में सोलर पार्क की स्थापना का कार्य प्रस्तावित किया गया तथा इस हेतु कुल 17 गांव की 626.822 हेक्टेयर शासकीय भूमि की मांग की गई थी जिसमें कुल 09 गांव की 377.423 हेक्टेयर भूमि जिला प्रशासन, राजनांदगांव द्वारा आबंटित की गई।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

भाजपाईयों के संरक्षण में अवैध रेत खदानों में माफिया का कब्जा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अवैध खनन माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के साथ ही प्रदेश में जंगल राज आ गया है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं। पूरे प्रदेश में अवैध माइनिंग का कारोबार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में फल-फूल रहा है। खनन माफिया भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इतने बेफिक्र हो गए हैं की खुलेआम माइनिंग अधिकारियों कर्मचारीयों की पिटाई कर रहे हैं। लगभग 9 दिन पहले गरियाबंद में खनिज इंस्पेक्टर सहित अनेकों कर्मचारीयों की पिटाई के बाद अब रायपुर जिले के आरंग के पास समोदा के हरदीडीह रेत घाट में खनिज विभाग के 16 अधिकारी, कर्मचारियों को अवैध खनन माफिया के लोगों ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। आरोप है कि उसके बाद खनिज विभाग के कर्मचारियों के द्वारा सील की गई मशीन खुलवाई गई और कार्यवाही का पत्रक भी फाड़ दिया। कार्यवाही के नाम पर प्रशासन लीपा-पोती में लगा हुआ है। ना मशीनें जप्त की गई और न ही गाड़ियां। इससे बेहद स्पष्ट है कि अवैध खनन माफियाओं को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है।

स्टेट जीएसटी विभाग ने कई फर्मों के प्रतिष्ठानों पर मारा छापा

रायपुर। स्टेट जीएसटी विभाग ने नई सरकार के गठन होने के बाद सक्रिय मोड पर आकर कर चोरी करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और विभाग में पारदर्शिता, निष्पक्षता और अनुपालन के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध और सतत प्रयासरत है। स्टेट विभाग द्वारा कर चोरी करने वाले व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कार्रवाई तेजी से की जा रही है। बुधवार को स्टेट जीएसटी विभाग के इंफोर्समेंट विंग ने कंधारी ट्रांसपोर्ट, कोरबा, फ्लावर क्रीन रायपुर और लक्ष्मी रूप प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। साथ ही, राजधानी रायपुर में एक तंबाखू गोदाम पर भी छापेमारी की। इन सभी से कुल 4 करोड़ रुपये का टैक्स मौके पर ही जमा करवाया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है ताकि अधिक राशि जमा कराई जा सके। स्टेट जीएसटी विभाग, छत्तीसगढ़ का मुख्य उद्देश्य है राजस्व बढ़ाना, जो सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर चोरी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा और विभाग संभावित सभी उपायों का उपयोग करके राजस्व बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारियों का तबादला

रायपुर. राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश के मुताबिक, कुल 18 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है. अजय कुमार अग्रवाल को सौमिल रंजन चौबे की जगह संचालक जनसंपर्क, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अधिकारी संवाद और संयुक्त परिवहन आयुक्त बनाया गया है. वहीं सौमिल रंजन चौबे को उपसचिव, कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. **किसे मिली कहां की जिम्मेदारी**-लीना कोसम परीक्षा नियंत्रक लोक सेवा आयोग, कमलेश नंदनी साहू, सीईओ सूरजपुर, देवनारायण कश्यप उप सचिव, वन विभाग, मंत्रालय, अरविंद पांडेय अपर कलेक्टर गरियाबंद, प्रेमप्रकाश शर्मा महाप्रबंधक, पाठ्य पुस्तक निगम, गोकुल कुमार रावटे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर, चेतन अवर सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, वैभव क्षेत्रज्ञ उप महाप्रबंधक संवाद एवं अवर सचिव खनिज विभाग, नंदकुमार चौबे संयुक्त कलेक्टर, बिलासपुर, के. आर. खूंटे विकास आयुक्त कार्यालय, रायपुर, अभिषेक अग्रवाल प्रबंध संचालक सीएसआईडीसी, ज्योति पटेल संयुक्त कलेक्टर, बिलासपुर, रवि सिंह संयुक्त कलेक्टर, रायपुर

ट्रैफिक नियम तोड़ा तो खैर नहीं पुलिस चलाएगी विशेष अभियान

रायपुर। राजधानी रायपुर में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए दुर्घटनाओं की रोकथाम और वाहन चालकों में सुरक्षा उपायों (हेल्मेट व सीट बेल्ट) का पालन कराये जाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस रायपुर द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शहर से गुरजने वाली रिंग रोड पर बिना हेलमेट दोपहिया और बिना सीट बेल्ट बांधे चार पहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस आने वाले दिनों में कार्रवाई तेज करने वाली है. बता दें कि मुख्य शहर की तरह ही नया रायपुर में भी लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं को देखते उनकी रोकथाम के लिए नया रायपुर के सभी प्रवेश मार्गो पर यातायात पुलिस के अधिकारी कर्मचारी चेंकिंग पाइंट लगाकर बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चालकों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही किया जाएगा. इस विशेष अभियान के दौरान आम लोग भी यातायात पुलिस के हेल्पलाईन नंबर 9479191234 पर बिना हेलमेट या सीट बेल्ट धारण किए वाहन चालक का फोटो खींचकर व्हाट्सप कर सकते है, जिसमें शिकायतकर्ता का नाम उजागर नहीं किया जाएगा. ऐसी शिकायत में फोटो के साथ गाड़ी का नंबर, स्थान का नाम व समय का उल्लेख आवश्यक होगा.

बस्तर में अब लाल सलाम नहीं जय श्री राम सुना जाएगा

रायपुर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भाजपा सरकार आने के बाद से बीते आठ सप्ताहों में बस्तर के हालात में आए बदलाव से विधानसभा में अवगत कराया उन्होंने कहा कि अब पूरा प्रशासन वहां है. आने वाले दिनों में बस्तर में लाल सलाम नहीं, जय श्री राम सुना जाएगा. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सदन में कहा कि बस्तर में आठ हफ्तों में 47 मोबाइल टावर लगाए गए. आठ हफ्तों में 35 किलोमीटर रोड बनी. आठ हफ्तों में 10 नये कैंप खोले गए. आठ हफ्तों में हैलीकॉप्टर की नाइट लैंडिंग फेसिलिटी शुरू हुई. बस्तर में हम विकास के कैंप खोल रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैं अभी सिलगेर गया था. वहां के एक पारा में पिछले एक साल से बिजली नहीं है. सिलगेर के बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं. कलेक्टर बनना चाहते हैं. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि देश को चुनौती देने वाले मुद्दे को दस फ़ीट नीचे ज़मीन में धँस जाना चाहिए और यहां हम भाजपा-कांग्रेस कर रहे हैं. ये वही टेकुलगुडम है, जहां घुसना आसान नहीं था. अब वहाँ कैंप खुल गया है. टेकुलगुड़म में कैंप खुला तो वहां जाना आसान हुआ है. हम अब पूर्ववर्ती की तरफ़ जाएंगे. हम अंदरूनी इलाक़ों में कैंप खोल रहे हैं. कैंप खुलेंगे तो कॉन्फ़्लिक्ट होगा. हमारा प्रयास नक्सलवाद को ख़त्म करने का है.

आवासीय कॉलोनी राज्य के लिए बने मिसाल

आवासीय कॉलोनी राज्य के लिए बने मिसालः चीफ जस्टिस सिन्हा

रायपुर। किसी भी जिले में न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये सर्वसुविधायुक्त रहवासी कॉलोनी उत्साहवर्धक एवं नयी उर्जा का संचार करने वाली होती है, जिससे उनके कार्यकुशलता में और दक्षता में वृद्धि होती है, जिले के नये कॉलोनी ऐसा बने जो राज्य के लिये एक मिसाल साबित हो। इस आशय के विचार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा के द्वारा मुंगेली जिले के ग्राम खेढ़ा में न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण के लिये रहवासी आवासीय कॉलोनी के वर्चुअल भूमिपूजन एवं शिलान्यास के अवसर पर व्यक्त किए। चीफ जस्टिस श्री सिन्हा ने आवास गृह निर्माण के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि न्यायालयों को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से काम किया जा रहा है और इसके लिए पहल भी शुरू कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि हमें राज्य के न्यायालयों में काम करने का बेहतर माहौल प्रदान करना है। यह परियोजना न्यायिक अधिकारी-कर्मचारियों के लिए आवास प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, ताकि आवास प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों और इंजीनियरों को इस परियोजना को पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा पर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री सिन्हा ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयीन अधिकारियों को भी इस परियोजना की सतत् निगरानी रखने के लिए भी कहा।

भूमि पूजन एवं आधारशिला के कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं पोर्टफालियो जज श्री नरेन्द्र कुमार व्यास द्वारा संबोधित करते हुए बताया कि जिला मुंगेली के न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये एक बी टाईप, एक ई टाईप, 3 जी टाईप, 16 एच टाईप एवं 9 आई टाईप शासकीय आवास गृह निर्माण की 04 करोड़ 84 लाख रूपए आबंटित की गई है। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण तय समय पर गुणवत्तापूर्वक किये जाने से जिला प्रशासन की विश्वसनीयता बढ़ती है।

क्रेडा द्वारा स्थापित संयंत्रों की मॉनीटरिंग एवं शिकायतों के निराकरण की प्रभावी व्यवस्था लागू

रायपुर। क्रेडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राजेश सिंह राणा ने क्रेडा द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की मॉनीटरिंग एवं उपभोक्ताओं से प्राप्त होने वाली शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए अत्यन्त प्रभावी व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत् सभी संयंत्रों का सतत् एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करने हेतु क्रेडा के संचालन एवं संधारण शाखा के अधिकारियों की टीम तैयार कर उन्हें जिम्मेदारी सौंपते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। क्रेडा द्वारा स्थापित तथा स्थापनाधीन संयंत्रों की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग हेतु पृथक से गुणवत्ता सेल का गठन किया गया है। साथ ही प्रधान कार्यालय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक गजट, वेब पोर्टल, टोल फ्री नम्बर के माध्यम से उपभोक्ताओं तथा अकार्यशील संयंत्रों से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने एवं उनके निवारण हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। इसके तहत् स्थापित समस्त संयंत्रों के निकट उपलब्ध हितग्राहियों, संस्थाओं, शिक्षकों, सरपंच एवं सचिवों इत्यादि के दूरभाष नम्बर प्राप्त कर उसका डाटाबेस तैयार कर उस डाटाबेस को इस प्रकार से रखा जाएगा कि अलग-अलग जिलों के कम से कम 4-5 हितग्राही या स्थल प्रत्येक दर्ज 100 की सूची में सम्मिलित हों, ताकि आकस्मिक एवं क्रम रहित सूची प्राप्त हो। गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक फील्ड अधिकारियों को बैठक के माध्यम से भी निर्देशित किया गया है। क्रेडा द्वारा रियल टाईम प्रगति हेतु जीयोटैग्ड फोटोग्राफ्स भी फील्ड से प्राप्त किये जाते है। उपयुक्त संचालन-संधारण हेतु क्रेडा द्वारा तकनीशियनों की क्लस्टर व्यवस्था लागू की गई है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.